



एमपी-यूपी में बाढ़ जैसे हालात

● वाराणसी में पुलिस चौकी डूबी; छत्तीसगढ़ में महिला पर बिजली गिरी

एजेंसी नई दिल्ली। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। मोडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 उड़ानें कैसिल हो गई हैं और 380 लेट हैं। यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रयागराज के दारागंज घाट का शमशान डूब गया, जिससे सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हुई। अशोकनगर में युवक बाइक समेत बह गया। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पैदल जा रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बिलासपुर में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोघा नदी में बह गए।



28 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 28 अगस्त तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए राज्य के 28 में से 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार के लिए किसी भी जिले में मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

हिमाचल प्रदेश में 98 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में 98 सड़कें बंद हैं। सड़क बंद होने के सबसे ज्यादा मामले मंडी में 49 रहे। इसके बाद कुल्लू में 28, कांगड़ा में 8, शिमला, सिरमौर और ऊना में 4-4, जबकि लाहौल-स्पीति में 1 सड़क बंद है। रविवार शाम से पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

काँकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मार्च करेगी

कहा- छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए, हमारे धैर्य को कमजोरी न समझें

एजेंसी नई दिल्ली। काँकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर-मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे, जिन्होंने NEET पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले CJP ने 20 जुलाई को भी जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। सोमवार को CJP ने अपनी वर्किंग कमेटी की वर्युअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। पार्टी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि छात्रों पर दर्ज केस खत्म होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। छट्ठकने नीट पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी की मांगों को लेकर 20

जून से जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। 25 जुलाई को सरकार से आश्वासन मिलने और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना आंदोलन खत्म

किया गया था। **सीजेपी बोली- वादे पूरे होने तक पीछे नहीं हटेंगे** सीजेपी नेता सौरव दास और रत्ना सिंह ने कहा कि सरकार को

सौरव दास बोले- लोकतंत्र के लिए संवाद जरूरी सौरव दास ने कहा, 'लोकतंत्र तभी काम करता है जब सरकार में बैठे लोगों और उन्हें चुनने वालों के बीच निरंतर संवाद हो। जब दोनों के बीच संचार टूट जाता है, तो समस्याएं और संघर्ष पैदा होते हैं।' वहीं, पार्टी ने सभी युवाओं, छात्रों, युवा संगठनों और छात्र संगठनों से 5 सितंबर को इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में इकठ्ठा होने और मार्च में शांतिपूर्वक भाग लेने की अपील की है।

किया था। 20 जुलाई को CJP ने संसद मार्च निकाला था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था।

20 जुलाई को CJP ने संसद मार्च निकाला था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

आंदोलन खत्म होने के बाद किए गए वादे पूरे करने चाहिए। सभी FIR वापस लेनी चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकनी चाहिए। वहीं, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दें।

जरांगे अनशन पर अड़े: मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार को दी डेडलाइन

कहा- मांगें नहीं मानीं तो 29 से भूख हड़ताल

एजेंसी मुंबई। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को 29 अगस्त से जालना जिले के अंतरवाली सराटी में भूख हड़ताल शुरू करने के अपने फैसले पर कायम रहने की बात कही। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग दोहराई।

मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 28 अगस्त तक की समयसीमा दी। जरांगे ने मांग की कि मराठा



समुदाय के पात्र सदस्यों को कुंभी प्रमाणपत्र और वैधता दस्तावेज जारी करने की लंबित प्रक्रिया 28 अगस्त तक पूरी की जाए। उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज

सभी मामले वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि समुदाय कानून के दायरे में और 1967 से पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा है।

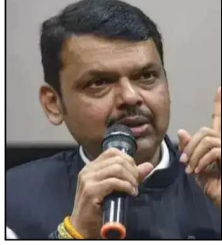
फडणवीस सरकार के मंत्रियों पर लगाए क्या आरोप?

अंतरवाली सराटी गांव में जरांगे और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच यह बैठक मीडिया और मराठा समुदाय के सदस्यों की मौजूदगी में हुई। जरांगे ने आरोप लगाया कि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और संजय शिरसाट मराठा समुदाय को आरक्षण देने की प्रक्रिया में अड़चन पैदा कर रहे हैं। मंत्री उदय सामंत ने कहा कि करीब 58 लाख रिकॉर्ड की जांच से कई संबंधित प्रविष्टियों की पहचान हुई है, जबकि कुछ रिकॉर्ड अभी अपलोड किए जाने बाकी हैं। हालांकि, जरांगे ने सवाल किया कि जांच किए गए कुल रिकॉर्ड में से वास्तव में कितने वैध कुंभी रिकॉर्ड की पहचान हुई है।

उन्होंने कहा कि जिन मराठाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में उनकी कुंभी पहचान साबित होती है, उन्हें कुंभी प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का रास्ता खुद रोका: फडणवीस

मुंबई(एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण और 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम पर तीखा हमला बोला है। फडणवीस ने चिदंबरम पर 'चुनिदा याददाश्त' रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का रास्ता खुद रोका है। फडणवीस ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम-2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में स्पष्ट प्रावधान है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। यह परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर किया जाना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण जनगणना में देरी हुई। ऐसे में जनगणना और उसके बाद परिसीमन का इंतजार करने पर महिला आरक्षण को 2029 के आम चुनाव से पहले लागू करना संभव नहीं होगा।



उत्तर प्रदेश व जापान के बीच संवाद से हुआ सकारात्मक माहौल का सृजन: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी व अन्य विभागों के अधिकारियों की लै बैठक

एजेंसी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को इन्वेस्ट यूपी व अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार 240 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश में आगमन हुआ। इस यात्रा में जापान व उत्तर प्रदेश के बीच सकारात्मक माहौल का सृजन हुआ। जापान से आए अतिथियों ने उत्तर प्रदेश में आए सकारात्मक बदलावों की सराहना की। ऐसे में जापान व उत्तर प्रदेश के बीच निरंतर संवाद कर निवेश के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को जापान के प्रतिनिधिमंडल की ओर से किए गए सभी एमओयू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि इस दौर का मुख्य फोकस निवेश, मैनुफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, तकनीक, कौशल विकास, शिक्षा और पर्यटन में सहयोग बढ़ाने पर रहा। मुख्यमंत्री जी ने ग्रीड के अंतर्गत जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने अवगत कराया कि 500 एकड़ में से 350 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जापान में सितंबर,

अक्टूबर व दिसंबर में होने वाले विभिन्न वैश्विक आयोजन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा जाए। इसमें मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, उद्योगपतियों के साथ ही संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जापानी भाषा के

● मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश व जापान के बीच निरंतर संवाद पर दिया जोर, बोले- इन्वेस्ट यूपी में अलग से बनाई जाए यामानाशी जापान डेस्क

● मुख्यमंत्री ने जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश

प्रशिक्षण तथा स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। यामानाशी प्रांत सहित जापान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी में अलग से यामानाशी जापान डेस्क बनाई जाए। इसके जरिए निरंतर संवाद होता रहे। उन्होंने हर तीसरे महीने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि इसी वजह से नागरिक समाज के सदस्यों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया गया है। संसद ने समिति को दोनों संविधान संशोधन विधेयकों की



जांच कर रही 31 सदस्यीय समिति

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 लाए गए हैं। विपक्ष की की मांग के बाद दोनों विधेयकों को चौधरी की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। पीपी चौधरी राजस्थान से भाजपा सांसद हैं। उन्होंने संसद परिसर में समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी।

मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज



सस्पेंड किया जाएगा। राज्य में 20 अगस्त से सरकार ने उन ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, जिन्हें मराठी नहीं आती है। मुंबई में हिंदी बोलने वाले ऑटो ड्राइवर्स ने

हड़ताल बुलाई है। सरकार ने 20 अगस्त से मराठी न बोलने वाले ड्राइवर्स को नोटिस देना शुरू कर दिया है। ड्राइवर्स ने कहा कि कई प्रदर्शनकारी मराठी सीखने

सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया

एजेंसी गुवाहाटी। मुंबई में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर्स ने सोमवार को सरकार के मराठी बोलने वाले नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाई है। गैर मराठी भाषी ड्राइवर्स का कहना है कि इससे उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। उम्रदराज ड्राइवर्स का कहना है कि हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। हमारे सामने परिवार को पालने की चुनौती है। 55-60 साल की उम्र में हम परिवार पालें या नई भाषा सीखें। यह बहुत मुश्किल है। 19 अगस्त को ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि ड्राइवर्स को पहले नोटिस देकर 3 महीने में

क्रिकेट के बहाने सत्ता, सुरक्षा और कूटनीति का अंदरूनी सच



पवन माकन
ग्रुप एडिटर, महानगर मेट्रो

पूर्व खुफिया एवं सुरक्षा अधिकारी यशोवर्धन आजाद की पुस्तक 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' इस यात्रा के कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाती है, जो बताते हैं कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में खेल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक गणनाएं होती रही हैं। पुस्तक में आजाद ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध, राजनीतिक हस्तक्षेप और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की है।

क्रिकेट को भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में अक्सर केवल खेल के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोनों देशों के इतिहास में क्रिकेट कई बार कूटनीति का माध्यम भी बना है और कई बार सुरक्षा तथा राजनीति की जटिलताओं का आईना भी। वर्ष 2004 का भारत का पाकिस्तान दौरा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक दशक से अधिक समय बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी। इसे 'मैत्री दौरा' कहा गया और उस समय दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें चल रही थीं। हालांकि मैदान पर दिखाई देने वाले खेल के पीछे सुरक्षा, खुफिया जानकारी और राजनीतिक निर्णयों की एक जटिल कहानी थी।

पूर्व खुफिया एवं सुरक्षा अधिकारी यशोवर्धन आजाद की पुस्तक 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' इस यात्रा के कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाती है, जो बताते हैं कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में खेल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक गणनाएं होती रही हैं। पुस्तक में आजाद ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध, राजनीतिक हस्तक्षेप और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की है।

वर्ष 2004 का पाकिस्तान दौरा से जुड़ा एक प्रसंग विशेष रूप से ध्यान खींचता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ कराची में एक टेस्ट मैच आयोजित करना चाहते थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा व्यवस्था ने कराची और पेशावर को टेस्ट मैच के लिए उपयुक्त नहीं माना था। आजाद उस समय भारतीय टीम की सुरक्षा से जुड़े दल में थे। सुरक्षा आकलन के बाद कराची और पेशावर में टेस्ट मैच नहीं कराने की सलाह दी गई थी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर को टेस्ट मैचों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया।

इसी बीच आजाद को तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का फोन आया। आडवाणी ने उनसे पूछा कि क्या कराची में टेस्ट मैच कराने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आजाद ने सुरक्षा संबंधी कारणों की जानकारी दी। इसके बाद उनसे आमल गया कि वे इस मामले को खुफिया ब्यूरो के निदेशक के सामने उठाएं। आडवाणी स्वयं भी इस संबंध में खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात करने वाले थे। आजाद के अनुसार, उन्हें यह जानकारी भी आश्चर्य हुआ कि यह आग्रह सीधे उपप्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा। बाद में उन्हें विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान संबंधी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी अरुण सिंह से पता चला कि यह स्वयं राष्ट्रपति मुशर्रफ़ का अनुरोध था। लेकिन अंततः सुरक्षा सलाह को प्राथमिकता दी गई और सुरक्षा दल द्वारा सुझाए गए कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया।

यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का अनुरोध था। लेकिन अंततः सुरक्षा सलाह को प्राथमिकता दे या सुरक्षा संबंधी सलाह को अंततः सुरक्षा आकलन को स्वीकार करना यह बताता है कि संवेदनशील मामलों में राजनीतिक नेतृत्व और पेशेवर सुरक्षा तंत्र के बीच संवाद तो जरूरी है, लेकिन निर्णय लेते समय सुरक्षा संबंधी



तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

2004 का पाकिस्तान दौरा सामान्य क्रिकेट दौरा भी नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध लंबे समय से राजनीतिक तनाव की छाया में रहे थे। ऐसे समय में भारतीय टीम का पाकिस्तान जाना दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की बड़ी कोशिश के रूप में देखा गया। मैदान पर खिलाड़ी थे, दर्शकों में उत्साह था और राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह संबंध सुधारने का अवसर था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए वही दौरा अत्यंत संवेदनशील अभियान था।

आजाद ने कराची में होने वाले एकदिवसीय मैच से पहले पैदा हुई सुरक्षा चिंताओं का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, भारतीय टीम को आतंकवादी खतरे की सूचना मिली थी। इसी दौरान 11 मार्च 2004 को स्पेन के मैड्रिड में रेलगाड़ियों में बम विस्फोट हुए, जिनमें 193 लोगों की मौत हुई और करीब दो हजार लोग घायल हुए। उस समय पाकिस्तान के कबायली और शहरी क्षेत्रों में अल-कायदा के शीर्ष कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बारे में भी खुफिया जानकारी थी।

भारतीय टीम की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे आजाद के सामने चुनौती केवल खतरे को पहचानने की नहीं थी, बल्कि यह तय करने की भी थी कि खिलाड़ियों को किसनी जानकारी दी जाए। उन्होंने टीम के प्रबंधक आर. एस. शेटी और प्रशिक्षक जॉन राइट के साथ इस सूचना को साझा किया और तत्काल इसे सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया। अगले दिन भारतीय टीम को कराची में एकदिवसीय मैच खेलना था।

इसके बाद इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारतीय टीम को आतंकवादी खतरे की सूचना मिली। यह सूचना खुफिया स्रोत से प्राप्त हुई थी और उसमें विशेष रूप से कराची तथा भारतीय टीम का उल्लेख था। हालांकि खतरे का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था, फिर भी इसे गंभीरता से लिया गया। टीम का सामान पहले ही तैयार

करवा दिया गया, ताकि मैच समाप्त होते ही भारतीय टीम सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो सके।

यह प्रसंग बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था केवल हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की नैनाती का नाम नहीं है। इसमें यात्रा की समय-सारणी, खिलाड़ियों की गतिविधियां, सामान की आवाजाही, आने-जाने के रास्ते, संभावित खतरे और आपात स्थिति में तत्काल निकासी की योजना तक शामिल होती है। किसी संवेदनशील देश में राष्ट्रीय टीम का दौरा अपने आप में एक जटिल सुरक्षा अभियान बन जाता है।

इस गंभीर वातावरण के बीच आजाद की पुस्तक में सचिन तेंदुलकर से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग भी है। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर तेंदुलकर ने काले सूट और काले ब्रीफकेस लिए खड़े सुरक्षाकर्मियों की ओर संकेत करते हुए मासूमियत से पूछा कि क्या वे ह्वापरमाणू बटनहू लेकर खड़े हैं। जब आजाद ने उन्हें जैमर के बारे में बताया तो तेंदुलकर ने उससे जुड़े कई सवाल किए। यह प्रसंग सुरक्षा के गंभीर संसार के बीच एक मानवीय और हल्का क्षण सामने लाता है। लेकिन 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' की महत्ता केवल ऐसे रोचक प्रसंगों में नहीं है। पुस्तक की वास्तविक उपयोगिता इस बात में है कि लेखक ने सत्ता, पुलिस और सुरक्षा तंत्र को भीतर से देखा है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह समझाया का प्रयास किया है कि अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप से निपटने वाली संस्थाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आज पहले से अधिक जटिल हो गया है। आतंकवाद के साथ-साथ साइबर अपराध, संगठित अपराध, सीमा पार से आने वाले खतरे और सूचना के दुरुपयोग जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे समय में सुरक्षा संस्थाओं की पेशेवर क्षमता के साथ उनकी जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

2004 का कराची टेस्ट प्रसंग इसी संस्थागत विवेक का

वन्देमातरम् विवाद- राष्ट्रगान पर राजनीति: विभाजन के प्रयास.....?

के छंदों को लेकर जंग छिड़ी है, पिछले नौ दशक से इसके दो ही छंद गाए जाते रहे हैं, जबकि इसके कुल मिलाकर आठ छंद हैं, अब देश के गृहमंत्री ने इसी को राजनीतिक विवाद की मुख्य बना दिया है तथा इसी आधार पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। गृहमंत्री का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम गुटिकरण के कारण फिर पुरानी गलती को दोहरा रही है।

वास्तव में इस विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के दिन उस समय हुई जब दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वज वंदन के समय सोनिया गांधी एक कार्यकर्ता को कोई निर्देश दे रही थी, आरोप है कि सोनिया ने राष्ट्रगान का अपमान किया और वे राष्ट्रभक्ति पसंद नहीं करती। यद्यपि आज तक प्रमुख सत्ताधारी दल भाजपा के भी किसी ध्वज वंदन

कार्यक्रम में 'वन्दे मातरम्' का पूरा गान गाते नहीं देखा गया, पिछले नौ दशकों से इसके प्रारंभिक दो छंद ही गाते देखा गया है, किंतु यह राजनीति की बलिहारी है, जिसने इसे राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना दिया और अब इस मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस के इस फैसले को आत्मघाती बता रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस गान को 1937 में 'राष्ट्रीय गान' का दर्जा दिया गया था। इसीलिए इसे आजादी के पहले की धरोहर मानकर पूरा राष्ट्र इसका सम्मान करता है और बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में झण्डा वंदन की सलामी के समय इसे गाया जाता रहा है, किंतु अब जक इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है तो इस गान के भविष्य को लेकर पूरा देश चिंतित है।

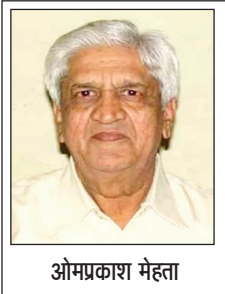
अब इस विवादित राजनीति का असर कहाँ-कहाँ तक होता है, यह फिलहाल कल्पना से परे है, क्योंकि पूरे देश की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में इसका पूरे सम्मान के साथ गान किया जाता है। अब फिलहाल यह भी मानना मुश्किल है कि इस विवाद के पीछे भी 'वोट बैंक' की राजनीति छुपी है, क्योंकि देश के दो विशेष वर्ग मुस्लिम और ईसाई आरोपित है कि इस गान का सम्मान नहीं करते? अब जो भी हो किंतु सबसे अहम बिन्दू यही है कि इस अहम् राष्ट्र भक्ति से जुड़े बिन्दू को राजनीति का अंग बनाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं कहा जा सकता।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

महंगी चीनी, आयात क्यों?

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, निर्यातक और खपत वाला देश है। उससे आगे ब्राजील ही है। एक अच्छे साल और अच्छी फसल के मद्देनजर भारत औसतन 70 लाख टन चीनी निर्यात करता रहा है, लेकिन 280-285 लाख टन की घरेलू खपत को सुनिश्चित करने के बाद ही निर्यात किया जाता है। इस साल भी तमाम स्थितियों के बाद 41 लाख टन से अधिक चीनी 'अतिरिक्त भंडारण' में है, फिर भी बीते गुरुवार, 20 अगस्त, को 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति सरकार ने दी है। बेशक यह चीनी शुल्क-मुक्त होगी। आयात की यह नौबत 10 साल के बाद आई है। मोदी सरकार ने 30 सितंबर, 2026 तक सभी तरह की चीनी के निर्यात पर पाबंदी थोप रखी है। दरअसल आई के बाद जब चीनी मिलों के बड़े व्यापारी और एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, तो उन्होंने दावा किया था कि इस साल 343.5 लाख टन चीनी का उत्पादन संभव है, लिहाजा निर्यात खोल दिया जाए। सरकार ने उनके आंकड़ों पर भरोसा किया और निर्यात खोल दिया, लेकिन जब हकीकत खुलने लगी, तो उत्पादन 279 लाख टन पर आकर ठहर गया, जबकि देश में चीनी की खपत 280-285 लाख टन आंकी गई है। नतीजा यह हुआ कि जो चीनी 21 जुलाई को करीब 45 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वह 31 जुलाई को उछल कर 50 रुपए हो गई और बीते शुक्रवार, 21 अगस्त, को 65 रुपए चीनी का भाव हो गया। एक ही महीने में चीनी 20 रुपए महंगीडू...। स्थितियों को भांपते हुए बड़े व्यापारियों, थोक विक्रेता, थोक के औद्योगिक उपभोक्ताओं ने जुलाई से पहले ही चीनी की जमाखोरी शुरू कर दी, ताकि त्योहारों के मौसम में अधिक दामों पर चीनी बेचकर मुनाफे कमाए जा सकें। अगस्त में कई चीनी मिलों ने बिक्री ही रोक दी। वे भी मुनाफाखोरी, कालाबाजारी की जमात में खड़ी हो गईं। अब 20 अक्टूबर को दशहरा है और 8 नवंबर को दिवाली है। भारत के दोनों ही राष्ट्रीय त्योहार हैं, लेकिन उनसे पहले ही चीनी की मिठास 'कड़वी' हो गई है। एथेनॉल को 'खलनायक' बनाया जा रहा है, जो सारासर गतत है। हालांकि हम ई-20 नीति के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि भारत सरकार तमाम पारदर्शी जवाब नहीं दे पाई है। ई-20 का देश में जरूरतस्त विरोध किया जा रहा है। नवंबर, 2025 से जुलाई, 2026 के दौरान तेल कंपनियों को 810.67 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई किया गया है। उसमें से 259.24 करोड़ लीटर, अर्थात 32 फीसदी, गन्ने से तैयार किया गया है, जबकि शेष 68 फीसदी एथेनॉल मक्का, शीरे, भारतीय खाद्य निगम के चावल और टूटे या सड़े-खराब अनाज से बनाया गया है। पहले 34 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए तय किया जाना था, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण 30 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने को मुहैया कराई गई। उसके बावजूद भंडारों में चीनी उपलब्ध थी। तो सवाल है कि चीनी का आयात क्यों किया जा रहा है? चीनी खुदरा बाजार में महंगी क्यों होती जा रही है? क्या जमाखोरों, मुनाफाखोरों, बिचौलिया ताकतों और वर्चस्ववादी मिलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये हाकालाबाजारीहद बार-बार उभर कर सामने आते हैं? इस खेल में बेचारा किसान तो गायब है। खुद भारत सरकार मानती है कि किसान की औसत आय 10,000 रुपए माहवार से भी कम है। तो महंगी चीनी के मुनाफे किसान की जेब में गए? जाहिर है कि जमाखोर दलाल 'अमीर' बनते रहे। दरअसल हम चीनी की कमी और महंगाई को न तो खाद्य-संकट मानते हैं और न ही यह राष्ट्रीय अराजकता का कारण बन सकती है। अलबत्ता मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेता 'राजनीति' जरूर करेंगे। बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में गन्ने की फसल, बीते साल सितंबर-अक्तूबर में, अधिक बारिश से प्रभावित हुई थी। नतीजतन उत्पादन कम हुआ और भंडारण 9 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस साल भी जून में बहुत कम बारिश हुई। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। मॉनसून भी असंतुलित रहा।



ओमप्रकाश मेहता

आज यदि सबसे अधिक दु:खी आत्मा होगी तो वह राष्ट्रभक्त बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय की होगी, जिनकी अनुपम कृति ह्रदयंदे मातरम्ह पर राजनीति हावी हो गई है। खासकर इस राष्ट्रीय गीत



मनोज कुमार अग्रवाल

नाबालिग बच्चों में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है। छोटी उम्र के बच्चों में आक्रामकता, चोरी, मारपीट और यहाँ तक कि गंभीर हिंसक अपराधों जैसे हत्या लूट के रज़ान में इजाफा देखा जा रहा है। इसके मुख्य कारणों में हिंसक डिजिटल कंटेंट, पारिवारिक संवाद की कमी और गलत संगत शामिल हैं।हाल ही में तेलंगाना के नालगोंडा में एक महिला प्रिंसिपल की उनके ही स्कूल के तरुण छात्र ने एक अन्य साथी छात्र के साथ मिलकर लूटपाट कर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने 48 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझा लिया है और दो छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर पैसों और आलीशान जीवन शैली के लिए अपराध की योजना बनाई थी।यह वारदात समाज में नाबालिग बच्चों में अपराध की दुनिया के प्रति बढ़ता आकर्षण कानून और समाज से बेखोफ उन्मुक्त और अव्यशी भरे जीवन शैली को जीने की ललक को बताती है। भारत में क्राइम के मामलों को लेकर एनसीआरबी ने चौकाने वाली रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक, हत्या, रेप और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता बढ़ी है। दिल्ली में 40 फीसदी से भी अधिक ऐसे केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि तेलगाना के कोंडमल्लेपल्ली स्थित नागार्जुन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर कल्लू रूपा रेड्डी 12 अगस्त की सुबह अपने घर में

मृत पाई गई। उनके शरीर पर चाकू के 27 घाव थे। उनका शव तब बरामद हुआ जब उनके पति, जो हैदराबाद में थे, ने पड़ोसियों को बताया कि वह उनके फोन का जवाब नहीं दे रही हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने उन्हें मृत पाया।

इसके बाद पुलिस ने पांच टीमें बनाई और सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य, फिंगरप्रिंट, तकनीकी डेटा और संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की और 80 से अधिक लोगों से पूछताछ की। बाबू शब्द के कारण छात्रों ने जांचकर्ताओं को तब सुपान मिला जब उन्हें पता चला कि फोन बंद होने से पहले रूपा रेड्डी ने अपनी चाची से बात करते समय बाबू शब्द का इस्तेमाल किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शरथ चंद्र पवार के अनुसार उसकी बातचीत के दौरान रिकॉर्ड किया गया आखिरी शब्द बाबू था। हमने इस बात की जांच की कि वह किसका जिन्न कर रही थी, और इससे हमें स्कूल के छात्रों की ओर संकेत मिला।

इसके बाद जांचकर्ताओं ने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और कक्षा 10 के उन पांच छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो स्कूल से अनुपस्थित रहे थे। उन्हें पता चला कि उनमें से दो छात्र पिछले कुछ दिनों में खूब पैसा खर्च कर रहे थे और पार्टियां दे रहे थे।पवार ने बताया कि दोनों छात्रों को बुधवार सुबह हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने योजना के अनुसार रूपा रेड्डी की हत्या की थी। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपियों को इससे पहले रूपा रेड्डी द्वारा फटकार लगाई गई थी, जब उनके छात्रावास के बैग से नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था।इसने उनके माता-पिता को सूचित किया, और उन्हें छात्रावास से निकालकर दैनिक छात्र का दर्जा दे दिया गया।पुलिस को संदेह है कि इससे प्रधानाचार्य के प्रति असंतोष पैदा होने में योगदान हो सकता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के इस दौर में ऑनलाइन गेम और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध असीमित और हिंसक सामग्री बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर डाल रही है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अपराध के

लगभग हर क्षेत्र में नाबालिग शामिल पाए गए। इसमें कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं। जिसमें रेप, हत्या और किडनैपिंग मे मामलों में 12 साल से कम उम्र तक के नाबालिग भी शामिल रहे। इस साल जनवरी 2026 में राजधानी दिल्ली में तीन नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तीनों पर एक 6 साल की बच्ची का रेप करने का आरोप था. कानूनन तीनों नाबालिग थे लेकिन तीनों ने मिलकर इतनी हैवानियत की थी कि वह बच्ची ठीक से चल भी नहीं पा रही थी. इसी तरह अप्रैल में नागपुर में पुलिस ने 13 नाबालिगों को पकड़ा था. इन सभी ने मिलकर एक 22 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या 100 रुपये के विवाद को लेकर हुई थी. आए दिन गंभीर अपराधों में नाबालिक अपचारीयों की बढ़ती भागीदारी समाजशास्त्र और बाल मनोविज्ञान के अध्येताओं के लिए चुनौती बन रही है। ये घटनाएं इतना बताने के लिए काफी हैं कि हमारे देश में अब नाबालिग तेजी से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं. हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है. इसमें सामने आया है कि दो साल में नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामलों में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में नाबालिगों के खिलाफ 30,555 मामले दर्ज किए गए थे. 2024 में यह बढ़कर 34,878 हो गए। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में दर्ज मामलों 58.9 लाख मामले दर्ज किए गए थे. 2023 की तुलना में यह 6 फीसदी की गिरावट थी. लेकिन इसके उलट, नाबालिगों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है. चिंता वाली बात यह है कि नाबालिग रेप, मर्डर, लूटपाट और किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराधों भी शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के 2,557 मामलों में नाबालिगों को आरोपी बनाया गया था. इसके अलावा मर्डर और किडनैपिंग जैसे 8,943 मामलों में आरोपी नाबालिग थे. 2024 में नाबालिगों के खिलाफ रेप के 1,067 और मर्डर के 1,120 मामले दर्ज किए गए थे.

अगर इसका औसत निकाला जाए तो हर दिन रेप और मर्डर के 3-3 मामलों में आरोपी नाबालिग होते हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में जितने नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 2,857 ही ऐसे थे जो अनपढ़ थे. 21,068 आरोपी ऐसे थे जिन्होंने 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की थी. जबकि, 10वीं से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले 8,301 और 12वीं पास 1,418 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया था.इसी तरह, इनमें से सिर्फ 2,216 नाबालिग ही ऐसे थे जो बेघर थे और जिनके माता-पिता नहीं थे. जबकि 36,905 आरोपी ऐसे थे जो अपने माता-पिता के साथ रहते थे. इनके अलावा 3,512 आरोप किसी न किसी गार्जियन के साथ रहते थे.

दरअसल माता-पिता का बच्चों के साथ संवाद कम होना, घरेलू हिंसा या परिवार का विघटन बच्चों को विद्रोही बना रहा है। पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में हट समय जीतने का भारी तनाव बच्चों में गुस्सा और कुंठा पैदा कर रहा है।बुरी संगत और सहपाठियों (पीयर प्रेशर) के दबाव में आकर बच्चे जल्दी गलत रास्ते पर कदम रख देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव है कि गरीबी कम करके बच्चों की शहरी वातावरण को बेहतर करके नाबालिगों को हिंसा में आने से रोका जा सकता है. अमीरी और गरीबी का अंतर अपराध को बढ़ाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपनी भड़ास निकालने के लिए हिंसा सबसे आसान जरिया बन जाती है. इसलिए गैर-बराबरी कम करने के साथ-साथ स्कूली शिक्षा को बेहतर करके बच्चों के हिंसा और अपराध से बचाया जा सकता है.इसके साथ ही माता-पिता बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें। बच्चों द्वारा देखे जाने वाले डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करें। घर और स्कूल में ऐसा वातावरण दें जहाँ बच्चा खुलकर अपनी बात रख सके।जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि उनकी काउंसलिंग कर उन्हें सुधारना है लेकिन इस सहानुभूति भरे कानून का नाबालिग अपचारी दुरुपयोग न करें इस ओर भी निगरानी जरूरी है।

गणपति आगमन जुलूस पर फेंके गए अंडे

मझगांव में दो गुटों के बीच झड़प के बाद हजारों लोग सड़कों पर

मुंबई। मझगांव इलाके मुंबई में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस घटना बाद रविवार देर रात से लेकर सुबह सोमवार तक तनाव बना रहा। त्योहार के आयोजकों का आरोप है कि पास की एक इमारत से जुलूस पर अंडे फेंके गए। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। भीड़ को हटाने से पहले सड़कों पर करीब 10,000-15,000 लोग जमा हो गए थे। सोमवार सुबह तक स्थिति काबू में आ गई थी और एहतियात के तौर पर इलाके में और गणेश पंडाल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अखिल पब्लिक फेस्टिवल कमेटी के अध्यक्ष हितेश जाधव ने आरोप लगाया कि भगवान गणपति के आगमन के बाद पास की एक इमारत से जुलूस पर अंडा फेंका गया। हितेश जाधव ने बताया कि आज यहां जो घटना हुई, वह निंदनीय है। भगवान गणपति का आगमन हो चुका था, और पास की इमारतों में से किसी ने ‘बैड’ (मराठी में अंडा) फेंका। जाधव ने कहा कि इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया और उन्होंने पुलिस से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की मांग की।

24 घंटे के अंदर एवशन का आश्वासन

आयोजक ने कहा कि हमने पुलिस से अनुरोध किया है कि वे अगले 24 घंटों के भीतर कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने आयोजकों को समर्थन दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जाधव ने कहा कि शीष शेलार ने हमारी बहुत मदद की है। हमें आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में 24 घंटे के भीतर पूरी कार्रवाई की जाएगी।

अचानक टूटा स्टीयरिंग रॉड, खाई के मुहाने पर अटकी बस...

संभाजीनगर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सूरत जा रही एसटी बस शनिवार को कन्नड़ घाट में हादसे का शिकार हो गई. अचानक स्टीयरिंग रॉड टूटने से बस अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार से टकराई और खाई के मुहाने पर अटक गई. बस में 59 यात्री सवार थे. हादसे में चार यात्री मामूली घायल हुए, जबकि 55 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से गुजरात के सूरत जा रही एसटी बस शनिवार को कन्नड़ घाट में बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई. बस का अचानक स्टीयरिंग रॉड टूट गया और देखते ही देखते चालक का नियंत्रण बस से हट गया. अनियंत्रित बस घाट की सुरक्षा दीवार से टकराई और खाई के मुहाने पर जाकर अटक गई. बस में उस वक्त 59 यात्री सवार थे. स्टीयरिंग फेल होने ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अगले पल क्या होने वाला है. यात्रियों को डर था कि बस सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरेगी. गनीमत रही कि बस का अगला हिस्सा लोहे के मजबूत स्पोंट में फंस गया और बस वहीं रुक गई. महज कुछ फीट और आगे बढ़ने पर बड़ा हादसा हो सकता था.

चार यात्री घायल, 55 को सुरक्षित निकाला गया

सुरक्षा दीवार से टकराने के दौरान बस के आगे बैठे चार यात्रियों को मामूली चोटें आईं. सभी घायलों को चालीसगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया. उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है. वहीं, बस में सवार बाकी 55 यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक टीम मौके पर पहुंची. राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया. इसके बाद क्रेन की मदद से बस को हटाया गया, जिससे घाट मार्ग पर यातायात फिर से सुचारु हो सका.

दूसरी बस से यात्रियों को मेजा गया सूरत

दुर्घटना के बाद यात्रियों के लिए दूसरी एसटी बस की व्यवस्था की गई. सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से दूसरी बस में बैठकर सूरत खाना किया गया. हादसे के बाद सुरक्षित बचे यात्रियों ने राहत की सांस ली और बस के रखरखाव को लेकर सवाल भी उठाए.

फिटनेस जांप पर उठे सवाल

इस घटना ने एसटी बसों के रखरखाव और फिटनेस जांच की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों का कहना है कि घाट जैसे जोखिम भरे रास्तों पर बसों को खाना करने से पहले उनकी तकनीकी जांच बेहद जरूरी है. यात्रियों ने मांग की है कि स्टीयरिंग रॉड टूटने की घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि बस को फिटनेस जांच के बाद ही सड़क पर उतारा गया था या नहीं.

नागपुर में वलोरिन गैस के रिसाव से हड़कंप

महानगर मेट्रो ब्यूरो
नागपुर। गोधनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरिन गैस रिसाव की घटना के बाद 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस प्लांट से दो सौ मीटर इलाके को प्रशासन ने नो मेंस लैंड घोषित कर दिया है. महाराष्ट्र के नागपुर में क्लोरिन गैस के रिसाव का मामला सामने आया है. क्लोरिन गैस के रिसाव से आसपास के घरों में लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर 40 लोगों को अस्पताल ले जाया गया. सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक नागपुर के मनकापुर थाना क्षेत्र के गोधनी में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. रविवार-सोमवार की रात करीब एक बजे इस प्लांट से क्लोरिन गैस का रिसाव शुरू हो गया. इस प्लांट के आसपास स्थित घरों में रहने वाले लोगों को अचानक ही सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई. पहले तो लोग यह समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है. दिक्कत बढ़ी और हर किसी को होने लगे, तब हड़कंप मच गया. हालात की जानकारी तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ के लोग भी मौके पर पहुंच गए. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर 40 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है. डॉक्टर्स के मुताबिक सभी की हालत खतरे से बाहर है. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें हालात को काबू करने की कवायद में जुट गई हैं. प्रशासन ने गैस लीक साइट से 200 मीटर के दायरे को नो मेंस लैंड घोषित कर दिया है. मनकापुर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हर्षा कालसेकर ने बताया कि गोधनी प्लांट से दो सौ मीटर की रेंज में स्थित सभी घर खाली करा लिए गए हैं. इस रेंज में किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है. उन्होंने लोगों से अप्रवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की और दावा किया कि इस घटना में किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचा है. मनकापुर इंस्पेक्टर ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम गैस रिसाव पर काबू पाने का प्रयास कर रही है.

महानगर मेट्रो

अचानक बदला कैबिनेट मीटिंग का समय

CM फडणवीस की ‘डिनर डिप्लोमेसी’ से सियासी अटकलें

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र में कैबिनेट बैठक का दिन अचानक बदलने के बाद महायुति नेताओं के डिनर से सियासी हलचल बढ़ गई है. बैठक को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन राज्य की राजनीति में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा तेज है. महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार का दिन हलचल भरा रहने वाला है. कैबिनेट की बैठक इस बार मंगलवार की जगह सोमवार दोपहर होगी. इसके बाद महायुति के बड़े नेता डिनर पर जुटेंगे. इससे पहले रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फडणवीस से वर्षा बंगले पर मुलाकात की थी. बैठक का दिन बदलने की आधिकारिक वजह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मंगलवार को मुंबई से बाहर एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना बताई गई है. मगर कैबिनेट बैठक के तुरंत

मराठी रिक्शा चालकों के पेट में लात मत मारें, Rapido, Ola, Uber को परमिशन पर संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार को खत

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत की ओर से राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखा गया है। उनकी ओर से पत्र के माध्यम से परिवहन मंत्री से अपील की गई है कि रैपिडो, ओला और उबर के चलते राज्य में हजारों की संख्या में ऑटो रिक्शा चला रहे मराठी युवकों को आजीविका से वंचित करना उचित नहीं है। संजय राउत ने पत्र में लिखा कि महोदय, राज्य के कुछ मंत्रियों के ‘रैपिडो’ कंपनी के साथ वित्तीय और व्यावसायिक संबंध हैं। ‘रैपिडो’ ने अब तक दही हांडी, गणेशोत्सव और कुछ मंत्रियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है और करोड़ों रुपये दिए हैं। कुछ मंत्रियों को चुनाव के लिए भी वनराशि दी है। इसलिए ऐसा लगता है कि हजारों रिक्शा चालकों को इनके नाम पर फंसाकर हमसान चुकाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने आगे लिखा कि जब महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री का मूल पेशा ही ‘रिक्शा चालक’ है, तो इस राज्य के रिक्शा चालकों की आजीविका छीनना उचित नहीं है। मैं इस मुद्दे पर रिक्शा चालक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ आपसे मिलना चाहता/चाहती हूं। कृपया उचित समय और स्थान की जानकारी दें। कृपया मुझे सूचित करें।

संजय राउत ने क्या कहा

संजय राउत ने बताया कि 16 अगस्त को नासिक के दौरे के दौरान, 100 से ज्यादा मराठी युवा उनसे मिले और अपनी आजीविका को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने रैपिडो, ओला और उबर के जरिए बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देने के सरकार के फैसले पर भी चिंता जताई और कहा कि इस कदम से मौजूदा ऑटो-रिक्शा ऑपरेटर सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। राउत ने यह भी दावा किया कि प्रस्तावित बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर ऑटो-रिक्शा चालकों में काफी

‘बहु चुपचाप सब देखती रही’, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय हत्याकांड में पिता ने लगाए गंभीर आरोप

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता (31) की हत्या में गिरफ्तार चारों आरोपियों को निहाल विहार पुलिस ने भले ही जेल भेज दिया है। लेकिन विनय के परिवार वालों का कहना है कि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। जिनमें एक मृतक विनय का ससुर और उनका चेचेरा भाई है। विनय की बहन कीर्ति और उनके पति दिव्यांश ने कहा कि उन्होंने 5 महीने 10 दिन के दो जुड़वा बच्चों को इसलिए अपनी सुपुर्दी में लिया है, क्योंकि उन बच्चों का ससुराल में रहना खतरे से खाली नहीं था। विनय की मां ने बताया कि दोनों जुड़वा बच्चों की दवाई को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ था। पोते की आंख के पास कोई दाग हो गया था, जिसके लिए दवाई लगाने के लिए विनय ने बोला था। इसी बात पर विवाद हुआ और फिर मामला बढ़ गया। पहले भी बहू के भाई आए थे और जान से मारने की धमकी देकर गए थे। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की।

दिल्ली में 5 साल से अटके अस्पतालों के लिए 426 करोड़ रुपये मंजूर, 691 बेड की होगी व्यवस्था

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। पांच साल से निर्माणाधीन पड़े दो अस्पतालों के अधूरे काम को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मादीपुर और ज्वालापुरी में बन रहे दोनों अस्पतालों के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 426.53 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। दोनों अस्पतालों के बनने से कुल 1382 नए बेड बढ़ेंगे। इससे नांगलाई, पश्चिमी दिल्ली, मादीपुर, ज्वालापुरी के आसपास रहने वाली 20 लाख आबादी वाले क्षेत्रों को फायदा होगा। मादीपुर और ज्वालापुरी अस्पताल का अभी तक 65 फीसदी काम पूरा हुआ है। दोनों ही 691-691 बैड के अस्पताल बनाए जाने हैं। साल 2019 में दोनों अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। 2022 में इनके डिजाइन में



बाद होने वाली गठबंधन नेताओं की बैठक ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है. फडणवीस के हालिया दिल्ली दौरे के बाद यह घटनाक्रम और ध्यान खींच रहा है.

मराठी रिक्शा चालकों के पेट में लात मत मारें, Rapido, Ola, Uber को परमिशन पर संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार को खत



नाराजगी है और उनके संगठन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए परिवहन मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो-रिक्शा चालकों ने अपनी चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 10 अगस्त को नासिक से मंत्रालय तक मार्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन राउत का दावा है कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या रिक्शा चालकों को लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी चिंताएं उठाने से रोका जाना चाहिए और सरकार से उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया।

अमित शाह को भी संजय राउत ने लिखा था खत

हाल ही में संजय राउत ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। 20 अगस्त को संजय राउत ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने और मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) कार्यालय के उद्घाटन पर चिंता व्यक्त की थी। संजय राउत की ओर से लिखे गए पत्र की प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय सहकारी समिति अध्यक्ष शरद पवार को भी भेजी गई थी। राउत ने शहरी सहकारी बैंकिंग परिसंपत्तियों से संबंधित मंत्रालय के हालिया निर्णयों पर अपनी प्रमुख आपत्तियां रखी थीं। राउत ने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर पत्र

‘बहु चुपचाप सब देखती रही’, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय हत्याकांड में पिता ने लगाए गंभीर आरोप



साढ़े तीन साल पहले हुई थी शादी

विनय की शादी लगभग साढ़े 3 साल पहले रेखा से हुई थी। इसी 17 मार्च उनके जुड़वा बच्चे हुए थे। विनय की छोटी बहन स्वाती ने बताया कि दो मॉडल मकान के सेकंड फ्लोर पर भैया और भाभी बच्चों के साथ रहते थे। छोटी-छोटी बातों को लेकर भाभी विवाद करती थी। बात-बात पर मायके वालों को बुलाने की धमकी देती थी। विनय की मां रेंु ने कहा कि वह, उनके पति और बेटी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। बहू खाना अलगा बनाती थी। दो दिन पहले भी बहू और बेटे के बीच कुछ अनबन हुई थी। जिसके बाद विनय 2 दिन

कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी. इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी. इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी. इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी. इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी. इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

बदलाव की अटकलें क्यों?

बैठकों का यह सिलसिला ऐसे समय सामने आया है, जब महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है. कैबिनेट की बैठक का अचानक एक दिन पहले होना, इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी. इसके बाद महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक वर्षा बंगले पर रखी गई है. इसमें फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच अहम बातचीत होगी. इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर रखा गया है. आधिकारिक तौर पर इसका मकसद आपसी तालमेल मजबूत करना, मतभेद सुलझाना और सरकार के कामकाज को रफ्तार देना बताया जा रहा है.

प्रताप सरनाइक से अपील

राउत ने अब सरनाइक से अपील की है कि वे इस पॉलिसी पर फिर से विचार करें और राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस को बढ़ाने से पहले ऑटो-रिक्शा ड्राइवर्स की चिंताओं पर ध्यान दें। 2025 में, महाराष्ट्र ने राज्य में गैर-कानूनी बाइक टैक्सी सर्विस के खिलाफ सख्त कदम उठाए। मंत्री सरनाइक ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मशियल तौर पर गाड़ियां चलाने के लिए सही परमिट की जरूरत होती है। इस मुहिम के तहत, एक घटना में 138 जवाहीर पर छापेमारी करके 72 गाड़ियां जब्त की गईं और आरटीओ व पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 93 के तहत, किसी भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को चलाने के लिए वैलिड परमिट लेना जरूरी है। हालांकि, यह पाया गया कि कुछ ऐप-बेस्ड कंपनियां और ड्राइवर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं।

से अपने प्लैट पर सोने भी नहीं जा रहा था। वारदात वाले दिन वह नहाने के लिए कपड़ा लेने गया था। तब भी बहू से उसकी कोई बात हुई। इसके बाद पता नहीं चला, क्या हुआ। बहू निकलकर घर से चली गई और बाद में फिर अपने दो भाई, पिता सहित कई लोगों को लेकर घर आ गई। वह पानी और नाश्ता लेने गईं इसी बीच में बहू के दोनों भाइयों ने विनय पर हमला शुरू कर दिया। बाकी जो लोग थे, उन्होंने विनय का हाथ पकड़ लिया था।

‘बहु सब कुछ चुपचाप देखती रही’

विनय के पिता ने कहा हमने काफी प्रयास किया की वह लोग विनय को छोड़ दें, लेकिन वह नहीं माने। एक ने बेटे का गला दबा दिया, दूसरा छतरी पर चढ़ गया। जिस कारण विनय की मौत हो गई। इस दौरान बहू वहीं थी। वह बस चुपचाप सब कुछ देखती रही। विनय की मां का कहना है कि बहू ने पूरी प्लानिंग के साथ बेटे की हत्या कराई।

ज्वालापुरी अस्पताल में भी पैसे को और जरूरत

इसी तरह ज्वालापुरी अस्पताल की भी शुरुआती लागत 319.65 करोड़ रुपये थी। अब इसकी लागत बढ़कर 484.04 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक 260.51 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। अब बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 223.53 करोड़ रुपये और लगेंगे। अब दोनों अस्पतालों के अधूरे काम को पूरा करने में दो साल और लगेंगे। 6 महीने प्लानिंग करने और 18 महीने उसे लागू करने में लगेंगे।

अहमदाबाद, (मंगलवार)

गजब! दिल्ली सरकार की 12,399 गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाणपत्र ही नहीं

उसके बाद महायुति के शीर्ष नेताओं का साथ बैठना इन चर्चाओं को और हवा दे रहा है. हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की बात से इनकार किया है. उनका कहना है कि फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं और राज्य से जुड़े कामकाज पर उनका ध्यान बना हुआ है. इन सब सियासी अटकलों के बीच रविवार को मुंबई में एक शिष्टाचार मुलाकात भी हुई. हरियाणा से आए सीएम नायब सिंह सैनी ने फडणवीस के सरकारी आवास ‘वर्षा’ बंगले पहुंचकर उनसे भेंट की. फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अब सबकी नजर सोमवार को होने वाली बैठकों पर है. कैबिनेट बैठक के बाद महायुति के नेता जब एक साथ बैठेंगे, तब उनकी चर्चा से राज्य की राजनीति को लेकर कुछ संकेत मिल सकते हैं.

गजब! दिल्ली सरकार की 12,399 गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाणपत्र ही नहीं

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच ‘दिया तले अंधेरा’ वाली स्थिति सामने आई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सुनवाई के दौरान सामने आया कि दिल्ली सरकार की 12,399 गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) ही नहीं है। मामले में एनजीटी ने बिना वैध प्रमाणपत्र वाले सरकारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने सरकारी और सरकारी कार्यों में लगी किराये की गाड़ियों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की अन्देखी को गंभीरता से लिया। यह सुनवाई जितेंद्र महाजन की ओर से दायर याचिका पर हुई। परिवहन विभाग ने अधिकरण को बताया कि वाहनों की निगरानी करने वाले कैमरे और सॉफ्टवेयर सरकारी तथा निजी वाहनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं।

कैमरे के सामने आते ही स्वतः बनता है चालान

परिवहन विभाग ने एनजीटी को बताया कि बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों के लिए व्यवस्था में रोक लगाई गई है। ऐसे वाहन के कैमरे के सामने आते ही उसकी पहचान हो जाती है और प्रणाली के माध्यम से स्वतः चालान जारी हो जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होती है। एनजीटी ने निर्देश दिए कि नियमों का केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकरण ने कहा कि बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के कोई भी सरकारी वाहन सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। इसके साथ ही अधिकरण ने संबंधित विभाग को नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

दिल्ली की जेलों में बंद गैंगस्टर्स पर कसेगा शिकंजा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर्स और हाई रिस्क विचाराधीन कैदियों पर अब और शिकंजा कसने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ऐसे कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि उनका वचंच ल तोड़ा जा सके। इसके लिए सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स (पंजाब अमेडमेंट) एक्ट, 2025 को दिल्ली में लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका मकसद जेल सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैदियों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण को संभव बनाना और संगठित अपराध से निपटने में राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है. दरअसल, मौजूदा व्यवस्था में विचाराधीन गैंगस्टर्स और कुख्यात अपराधियों को दिल्ली से दूसरे राज्य की जेल में भेजना संभव नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 के तहत अंतरराज्यीय ट्रांसफर का प्रावधान आरोप साबित हो चुके कैदियों के लिए है। वहीं, विचाराधीन कैदियों का मामला संबंधित ट्रायल कोर्ट के रिमांड वारंट और रिजनर्स एक्ट, 1900 के तहत आता है, जो राज्य के भीतर कैदियों के ट्रांसफर की अनुमति देता है। इस कमी को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स (पंजाब अमेडमेंट) एक्ट, 2025 पेश किया था। इसे 21 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसमें सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या जनहित के आधार पर विचाराधीन कैदियों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में भेजने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार अब इसी संशोधित व्यवस्था को राजधानी में लागू करने का प्रस्ताव लाई है। सरकार का कहना है कि कुछ कुख्यात विचाराधीन कैदी जेल मे रहते हुए भी स्थानीय नेटवर्क और दूसरे गिरोहों से संपर्क बनाए रखते हैं। इससे वे अपने आपराधिक गठजोड़ को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे कैदियों के बीच गैंगवार मामलों भी सामने आते रहते हैं। सरकार के अनुसार, ऐसे कैदियों को दिल्ली से बाहर की जेलों में भेजने से गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे की कार्रवाई में बाधा डालने की उनकी क्षमता कम की जा सकती है। वहीं, मॉडल प्रिजन एड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023 की धारा 20 में भी कैदियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर का प्रावधान है। इसमें विचाराधीन कैदी को भी दूसरे राज्य की जेल में भेजने की व्यवस्था है। इसके लिए ट्रायल कोर्ट की सहमति जरूरी बताई गई है। दिल्ली में इस संशोधित कानून के लागू होने से इससे जेल सुरक्षा और प्रबंधन मजबूत होगा।

MBBS की सीट के नाम पर 90 लाख की ठगी

महानगर मेट्रो ब्यूरो
नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में बेटे को एमबीबीएस की सरकारी सीट दिलाने का झांसा देकर हरिद्वार निवासी एक पूर्व सैन्य अधिकारी से 90 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मनोज नामक व्यक्ति ने खुद को रेडियोलॉजिस्ट और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का सदस्य बताकर पीड़ित को भरोसे में लिया। दोनों की मुलाकात 20 जुलाई 2025 को कर्नाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में हुई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने दाखिले के लिए 90 लाख रुपये की मांग की। पीड़ित ने 7.50 लाख रुपये ऑनलाइन भेजे, जबकि 82.50 लाख रुपये नकद दिए। रकम जुटाने के लिए उन्होंने अपना मकान बेचने, पेंशन निधि लगाने और परिवार से उधार लेने की बात कही है। आरोप है कि नकद राशि कर्नाट प्लेस के डी-ब्लॉक पार्किंग के पास एक रेस्तरां के नजदीक दी गई।



दिल्ली में स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में स्वाइन फ्लू और वेक्टर जनित बीमारियों की मौजूदा स्थिति और रोकथाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों, अस्पतालों की तैयारियों, निगरानी व्यवस्था और संभावित मामलों को लेकर विभागीय तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में खास तौर पर स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की स्थिति पर नजर रखने और इनके प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने के साथ-साथ आने वाले दिनों में बीमारियों की रोकथाम के लिए फील्ड स्तर पर निगरानी और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को और मजबूत करने को लेकर भी दिशा-निर्देश दे सकते हैं। दिल्ली में मानसून के दौरान वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने को देखते हुए सरकार की ओर से इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इससे पहले सफ़दरजंग अस्पताल ने अपने एक बयान में कहा कि अस्पताल स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया कि मरीजों की जरूरत और मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से इलाज किया जाता है, साथ ही अस्पताल मामलों पर नजर रखता है और जरूरी इंतजाम बनाए रखता है। बता दें हाल के हफ्तों में दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्ली में एच।एन।ए के 1,777 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि राजधानी में इन्फ्लुएंजा-ए के भी 2,300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं।

महाराष्ट्र में रिक्शा चला रहे हजारों युवकों को आजीविका से वंचित करना उचित नहीं

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए परिवहन मंत्री से अपील की है कि रैपिडो, ओला और उबेर के चलते राज्य में हजारों की संख्या में रिक्शा चला रहे मराठी युवकों को आजीविका से वंचित करना उचित नहीं है। राउत ने पत्र में लिखा- महोदय, राज्य के कुछ मंत्रियों के रैपिडो कंपनी के साथ वित्तीय और व्यावसायिक संबंध हैं। रैपिडो ने अब तक दही हांडी, गणेशोत्सव और कुछ मंत्रियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है और करोड़ों रुपए दिए हैं। कुछ मंत्रियों को चुनाव के लिए भी धनराशि दी है। इसलिए ऐसा लगता है कि हजारों रिक्शा चालकों को इनके नाम पर फंसाकर एहसान चुकाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने आगे लिखा- जब महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री का मूल पेशा ही रिक्शा चालक है, तो इस राज्य के रिक्शा चालकों की आजीविका छीनना उचित नहीं है। मैं इस मुद्दे पर रिक्शा चालक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ आपसे मिलना चाहता हूं। उचित समय और स्थान की जानकारी दें। कृपया मुझे सूचित करें। हाल ही में संजय राउत ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। 20 अगस्त को संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने और मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम कार्यालय के उद्घाटन पर चिंता व्यक्त की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत की ओर से लिखे गए पत्र की प्रति सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार को भी भेजी गई थी। राउत ने शहरी सहकारी बैंकिंग परिप्रेक्षितियों से संबंधित मंत्रालय के हालिया फैसलों पर आपत्तियां रखी थीं। राउत ने कहा था कि उन्होंने जानपूझकर पत्र मराठी में लिखा है ताकि जनता समझ सके कि उनके शब्दों में, महाराष्ट्र के शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के साथ किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया था और एनयूसीएफडीसी के जरिए महाराष्ट्र और गोवा के शीर्ष शहरी सहकारी बैंक की संपत्ति को उसके सदस्यों की सहमति के बिना जब्त कर लिया गया था। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन पर सीधा हमला बताया था।

बारिश का कहर : सोनभद्र में कनहर बांध के फाटक खुले, हिमाचल में 125 सड़के बंद

सोनभद्र (एजेंसी)। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया है। सोनभद्र जिले में कनहर बांध सिंचाई परियोजना के कैचमेंट परियामें लगातार वर्षा के चलते अमवार स्थित कनहर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी बारिश और भूस्खलन की चपेट में है, जहां 125 से अधिक सड़के बंद हो गई हैं। सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर 262.350 मीटर पर पहुंचने के बाद, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई विभाग ने तत्परता दिखाकर बांध के छह फाटक (संख्या 2, 4, 5, 6, 11 और 13) खोल दिए हैं। फाटकों के खुलने से कनहर नदी के डाउनस्ट्रीम में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है और नदी उफान पर है। प्रशासन ने तटीय और दूब क्षेत्रों में आम लोगों तथा मवेशियों के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

तमिलनाडु में 1.30 करोड़ परिवारों को मिलेंगे सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर

–विजय सरकार ने ‘अन्नपूर्णी सुपर 6’ योजना का किया ऐलान



परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई और कीमतों में वृद्धि से पिछले चार महीनों में परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इसके चलते कई परिवार वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने को मजबूर हुए। सरकार का उद्देश्य एलपीजी पर होने वाले खर्च की भरपाई कर परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना है।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ेगा

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा और आवागमन से जुड़ी ‘वेद्री पयानम’ योजना के विस्तार की भी घोषणा की। इसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा बढ़ाई जाएगी। योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। इसके तहत महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस और डेल्टाक्स सरकारी बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री मुफ्त यात्रा कर

सकेंगे। जिलों के बीच आवागमन के लिए मुफ्रिस्तल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराया वाली बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार के अनुसार ‘वेद्री पयानम’ के क्रियान्वयन पर करीब 6,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होने का अनुमान है। इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं होगी और मुफ्त यात्राओं की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने ‘वेद्री विजन डॉक्यूमेंट’ के तहत महिला सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और आजीविका को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान किए जाने की जानकारी दी। इनमें ‘सिंगा पेन’ स्पेशल टास्क फोर्स, ‘थैमानम थंगामोथिरम’, ‘वेद्री मर्गलिर आडुगल वलरप्पु’ और ‘अन्नानिन सीर’ जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।

क्लोरीन गैस लीक होने से 40 लोग प्रभावित, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत

-सभी को अस्पताल में कराया मर्ती, 5 गंभीर को आईसीयू में किया शिफ्ट

नागपुर, एजेंसी। नागपुर में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के गोधनौ इलाके में सोमवार को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। गोधनौ नगर पंचायत द्वारा संचालित

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव की घटना के बाद करीब 40 लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रभावित लोगों में संयंत्र के 8 से 10 कर्मचारी और आसपास रहने वाले 20 से 25 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में रखा है। वहीं, विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विस्तृत अनुशंसाएं प्रस्तुत करेंगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिससे इसकी निष्पक्षता और गंभीरता सुनिश्चित हो सकेगी। समिति को तीन माह के भीतर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

अमरावती के सरकारी अस्पताल में आग, वेंटिलेटर फटा 3 शिशुओं की मौत

अमरावती, एजेंसी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित एक सरकारी अस्पताल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में आग लगने से कम से कम तीन नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जिंदगी की शुरुआत करने वाले इन नवजात शिशुओं ने अभी अपनी मां को जीभर कर देखा भी नहीं होगा कि इस दर्दनाक हादसे ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि यह आग नियोनेटल यूनिट में एक वेंटिलेटर में विस्फोट होने के कारण लगी। यह भयावह घटना बुधवार तड़के करीब 3~30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार, नियोनेटल यूनिट में एक वेंटिलेटर में हुए धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और पूरे वार्ड में धुआं भर गया। उस समय यूनिट में कुल 39 नवजात शिशु भर्ती थे। इयूटी पर मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वार्ड को खाली करवाना शुरू कर दिया। इस दौरान छह नवजातों को गंभीर हालत में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया



गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, तीन नवजातों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। आग इतनी भीषण थी कि एनआईसीयू वार्ड की स्थिति देखकर अंदजा लगाया जा सकता है। वार्ड में मौजूद बेड, मशीनें और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए, बिस्तर राख के ढेर में बदल गए। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने पूरी कोशिश की कि बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन धुएं की वजह से तीन मासूमों को

नहीं बचाया जा सका।घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने इस पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि आग लगने का जिम्मेदार कौन है और अस्पताल में आग बुझाने के लिए क्या इंतजाम थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संसद का सत्रावसान अब तक क्यों नहीं? कांग्रेस ने उठाए सवाल

-जयराम बोले- क्या परिसीमन बिल के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं अमित शाह?

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आशंका जताते हुए सवाल किया है, कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब भी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आमतौर पर लोकसभा की कार्यवाही

अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और सत्रावसान के बीच दो से चार दिन का अंतर होता है। हालांकि कई मौकों पर दोनों प्रक्रियाएं एक ही दिन भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्रावसान को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

2015 और 2021 का उदाहरण दिया कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2015 के मानसून सत्र में स्थगन और सत्रावसान के बीच 28 दिन तथा 2021 में 20 दिन का अंतर रहा था। हालांकि, उनका दावा है कि उन मौकों पर मौजूदा जैसी परिस्थितियां नहीं थीं। उन्होंने सवाल किया कि इस बार इतनी असामान्य देरी क्यों हो रही है। ऐसे में जयराम रमेश ने पूछा कि क्या सरकार किसी विशेष सत्र के जरिए परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी कर

रही है और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में संसद की कार्यप्रणाली और नियमों पर आधारित एम.एन. कौल और एस.एन. शकधर की पुस्तक ‘प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ का एक पृष्ठ भी साझा किया है।

राष्ट्रपति के आदेश से होता है सत्रावसान

किताब के हवाले से कांग्रेस नेता ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से संसद के सत्र की औपचारिक समाप्ति हो सकती है। राष्ट्रपति इस संबंध में प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। आमतौर पर सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सत्रावसान किया जाता है, हालांकि यह पहले भी हो सकता है।

कांग्रेस ने 543 सीटें स्थिर रखने की मांग की

कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 वर्षों तक स्थिर रखने की मांग दोहराई है। पार्टी का कहना है कि इसी मौजूदा संख्या पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए और इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने भी महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के अपने संकल्प को दोहराया है।

अप्रैल में विधेयक नहीं जुटा पाया था दो-तिहाई बहुमत

कांग्रेस के अनुसार, 17 अप्रैल को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत

मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में भगदड़, छह श्रद्धालु घायल, सावन के आखिरी सोमवार को हुआ हादसा

पटना (एजेंसी)। मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर धाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर बड़ा हादसा होते-होते बवा। मंदिर में दर्शन और जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मुख्य द्वार पर भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम छह श्रद्धालु घायल हो गए। यह घटना सोमवार सुबह लगभग 6~25 से 7 बजे के बीच उस समय हुई जब भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। घायलों को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ का दबाव बढ़ा, कुछ लोगों ने नियंत्रण खो दिया और अफरा-तफरी मच गई। स्थिति भगदड़ में बदल गई, और इस दौरान कुछ श्रद्धालु नीचे गिर गए। भीड़ के दबाव में दबने से कई लोगों को चोट आई। सूचना के अनुसार, इस घटना में चार महिलाएं और दो पुरुष समेत कुल आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर हैं। मौके पर पहले से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। स्थिति बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। स्थानीय संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस का सहयोग किया और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद की। उन्होंने गिरे हुए लोगों को उठाया और घायल श्रद्धालुओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालकर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। सावन की अंतिम सोमवारी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुरख़ा इंतजाम किए गए थे और स्वयं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भी मंदिर की व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए थे। हालांकि, सुबह अचानक मुख्य गेट पर भीड़ का अत्यधिक दबाव बढ़ जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति को जल्द ही संभाल लिया गया और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया।

पेपर लीक रोकने के लिए बिहार सरकार ने बनाई समिति



कैलेंडर के निर्माण, प्रश्न पत्रों में सुधार, परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने और पेपर लीक की रोकथाम के प्रभावी उपायों को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव देगी। इस समिति द्वारा परीक्षा संचालन, प्रश्न-पत्र निर्माण, मूल्यांकन, परिणाम घोषणा और शिकायत निवारण सहित पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए

व्यापक अनुशंसाएं की जाएंगी। प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित टैंकों के लिए चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल विकसित करने पर भी विशेष विचार किया जाएगा, ताकि हर स्तर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समिति परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन

पाकिस्तानी गैंगस्टर की सक्रियता ने पंजाब में बढ़ाई टेंशन

-शहजाद भट्टी निशाने पर, हाई अलर्ट जारी

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब में एक बड़ी आतंकवादी घटना की साजिश रचे जाने की गंभीर आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों की नौद उड़ा दी है। खुफिया एजेंसियों द्वारा राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इस खतरनाक योजना के तहत, दो महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी भी की जा चुकी है, जिसने सुरक्षा प्रतिष्ठानों में खलबली मचा दी है। हालांकि, इन आशंकाओं को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खुफिया इनपुट की गंभीरता को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा

व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी गुर्गें विशेष रूप से अमृतसर जिले में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला करने की फिराक में हैं। यह संवेदनशील जानकारी पंजाब पुलिस सहित देश की अन्य सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की गई है। एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस इनपुट को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और तत्काल प्रभाव से सभी संवेदनशील स्थानों, विशेषकर सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाए। इस अलर्ट के बाद, सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है और सदिध ऑफेंसिव्स की पहचान राणा भाई और मलिक के रूप में हुई है। खुफिया इनपुट के हवाले से बताया गया है कि साजिश के तहत अमृतसर के खासा छवनी

विस्तृत रेकी की गई है। यह बात और भी चिंताजनक है कि खासा छवनी में कुछ समय पहले ही एक रहस्यमय धमाका हुआ था, हालांकि उस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और विस्फोट छवनी की बाउंड्री

वॉल के पास हुआ था। जाचकर्ताओं को संदेह है कि उस धमाके के तार भी किसी पूर्व नियोजित साजिश से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अब तक पिछली घटना और मौजूदा इनपुट्स के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका है। सुरक्षा एजेंसियां इन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ भारत में पहले से ही व्यापक कार्रवाई चल रही है। यह गिरोह धार्मिक और संवेदनशील स्थानों पर हमला करने, साथ ही राजनीतिक नेताओं को

निशाना बनाने की साजिशों में शामिल रहा है। हासिल नहीं कर सका था। मत विभाजन में शामिल 528 सांसदों में 298 ने विधेयक के पक्ष और 230 ने विरोध में मतदान किया। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद जयराम रमेश

ने दावा किया था कि सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है और वह इसे हासिल नहीं कर पाएगी। अब मानसून सत्र के औपचारिक सत्रावसान में देरी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।



सोने के भाव में तेजी, चांदी की कीमत फिसली

सोना 1,132 रुपए तेज होकर 1,63,570, चांदी 1,000 रुपए गिरकर 2,45,597 एर



नई दिल्ली।

सोना अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की अग्रत्याशित बायबैक की घोषणा के बाद सोने की कीमतों में वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में तेजी दर्ज की गई है। इस कदम ने निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की ओर बढ़ा दिया है, जबकि चांदी के भावों में सुस्ती का रुख देखने को मिला। वै श्विक बाजार में सोना 4,700 डॉलर प्रति औंस के करीब, जबकि चांदी 69 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 386 रुपये की गिरावट के साथ 1,62,052 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 1,62,438 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 1,132 रुपये की तेजी के साथ 1,63,570 रुपये के भागव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 1,63,585 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 1,62,001 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,45,597 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 2,46,597 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 461 रुपये की गिरावट के साथ 2,46,136 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 2,46,475 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 2,44,815 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। चांदी के वायदा भाव ने इस साल 4,20,048 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के वायदा भाव तेजी और चांदी के नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉमेक्स पर सोना 4,673.40 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 4,680.60 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 25.70 डॉलर की तेजी के साथ 4,706.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 5,586.20 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 69.34 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला बंद भाव 69.53 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 0.37 डॉलर की गिरावट के साथ 69.16 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके भाव ने इस साल 121.79 डॉलर का उच्चतम स्तर छू लिया।

होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स का शेयर बाजार में मिला-जुला असर

नई दिल्ली।

ब्लैकस्टोन समर्थित होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को शेयर बाजार में मिला-जुला डेब्यू किया। कंपनी का निर्गम मूल्य 60 रुपये प्रति शेयर था, जिसके मुकाबले बीएसई पर शेयर 0.58 प्रतिशत टूटकर 59.65 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जबकि एनएसई पर इसने 0.41 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 60.25 रुपये पर शुरुआत की। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 16,873.63 करोड़ रुपये रहा।

2,600 करोड़ रुपये के इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह बोली के अंतिम दिन 1.45 गुना अधिदान मिला था। कंपनी ने अपने शेयर के लिए 57-60 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था। आईपीओ से पहले, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स ने एंकर निवेशकों से 1,168 करोड़ रुपये जुटाए थे। आईपीओ की राशि मुख्य रूप से कर्ज चुकाने में प्रयोग होगी।

होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास, स्वामित्व और संचालन का काम करती है। यह 10 शहरों में करीब छह करोड़ वर्ग फुट के 46 परिसरपंतियों का प्रबंधन करती है।

अमेरिका-भारत के शेयर महंगे, यूरोप में ज्यादा आकर्षक एफसीएफ यील्ड- रिपोर्ट

यूरोपीय इक्विटी भारतीय-अमेरिकी बाजारों से अधिक आकर्षक, निवेशक अब ‘वैल्यू’ बाजारों पर केंद्रित

नई दिल्ली।

एक ताजा वैश्विक रणनीति रिपोर्ट में कहा है कि जैसे-जैसे मूल्यांकन बढ़ रहे हैं, अमेरिका और भारत के शेयर बाजार, फ्री कैश फ्लो (एफसीएफ) यील्ड के मामले में कम आकर्षक होते जा रहे हैं जबकि यूरोप जैसे वैल्यू-ओरिएंटेड मार्केट काफी ज्यादा यील्ड दे रहे हैं। फ्री कैश फ्लो यील्ड असल में किसी कंपनी द्वारा अपने बाजार मूल्य के मुकाबले सृजित की गई वास्तविक नकदी

का प्रतिशत में मापने का पैमाना होता है। चूंकि अमेरिकी बाजार महंगे लगने लगे हैं, इसलिए निवेशक दूसरे बाजारों की ओर देख रहे हैं, जहां कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और मूल्यांकन के हिसाब से अभी भी आकर्षक हैं। उनका ज्यादा ध्यान एशिया के बाजार यूरोप पर है। टेक-प्रधान एसएंडपी 500 इंडेक्स का एफसीएफ यील्ड 2.7 फीसदी है जबकि यूरोपीय इक्विटी के बड़े इंडेक्स स्टॉक्स 600 का

एफसीएफ यील्ड 5 फीसदी है। निफ्टी 50 के लिए भी यह आंकड़ा 2.7 फीसदी है, जो एसएंडपी 500 के बराबर है, लेकिन इसमें एआई का कोई योगदान नहीं है। फ्री कैश फ्लो यील्ड एक वित्तीय पैमाना है, जो कंपनी के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले नकदी सृजित करने की क्षमता बताता है। यह संख्या जितनी ज्यादा होती है, नकदी पैदा करने की क्षमता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। पिछले कुछ सालों

में अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के पूंजीगत खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय संकट के बाद के लगभग एक दशक में ये कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगीं। उन्हें सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग से फायदा हुआ और साथ ही डैट कॉम दौरे में किए गए पूंजी निवेश का भी लाभ मिला। उन्हें कम पूंजी की जरूरत थी और शून्य व्याज दरों की वजह से उन्हें अच्छे मूल्यांकन का फायदा मिला।

आरबीआई के रियायती स्वेप से रुपया बेअसर, अरबों डॉलर भंडार में, बाजार में नहीं

2013 के विपरीत इस बार डॉलर बाजार में जारी नहीं हुए, मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रियायती स्वेप योजनाओं के तहत भारत में अरबों डॉलर का प्रवाह हुआ है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका रुपये की विनिमय दर पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 21 अगस्त तक अगर कुल 72.85 अरब डॉलर से अधिक की यह विदेशी मुद्रा सीधे केंद्रीय बैंक के भंडार में जमा हो गई है, बजाय इसके कि यह हाजिर बाजार में रुपये को मजबूती देती। यह स्थिति 2013 की समान योजना से बिल्कुल विपरीत है, जब रुपये में महत्वपूर्ण मजबूती देखी गई थी। आरबीआई ने 8 जून को रियायती स्वेप योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत, बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी-बैंक (एफसीएनआर-बी) जमाओं के माध्यम से जुटाए गए डॉलर को रिजर्व बैंक के पास जमा कर रुपये प्राप्त करते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था में रुपये की नकदी तो बढ़ी है, लेकिन विदेशी मुद्रा सीधे आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में जुड़ गई है। परिणामस्वरूप, रुपये की विनिमय

अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट, ईरान पर सख्ती से पहले कच्चे तेल में गिरावट

निवेशकों ने की मुनाफावसूली, ब्रेंट क्रूड 1.3 और डब्ल्यूटीआई 1.6 फीसदी गिरा

नई दिल्ली।

ईरान पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा से पहले सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने पिछले सप्ताह की तेजी के बाद मुनाफावसूली की, वहीं अमेरिका द्वारा ईरान के आर्थिक संबंधों को निशाना बनाने की तैयारी ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 1.3 फीसदी गिरकर 93.16 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.6 फीसदी फिसलकर 85.70 डॉलर पर पहुंच गया। यह निवेशकों की मुनाफावसूली और आगामी अमेरिकी प्रतिबंधों की अनिश्चितता का परिणाम था। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई बताया है, जिसका लक्ष्य ईरान के आर्थिक संबंधों पर दबाव बढ़ाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान की मदद करने वाले देशों को चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ी है। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को दबाव और हताशा बताते हुए खारिज किया है और आर्थिक दबाव से निपटने के रास्ते तलाशने की बात कही।

24 से 31 अगस्त के बीच 9 आईपीओ, निवेश से पहले जोखिम समझें

नईदिल्ली। शेयर बाजार में इस सप्ताह आईपीओ की जोरदार हलचल है। 24 से 31 अगस्त के बीच नौ कंपनियां करीब 3,500 करोड़ जुटाने के लिए बाजार में उतर रही हैं। इनमें फार्मा, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, टेक्सटाइल, प्रोजेक्ट्स और पावर सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं।

सबसे बड़ा इश्यू सिम्बायोटेक फार्मालैब का 1,757 करोड़ का है। कंपनी एपीआई, न्यूट्रिशनल और स्पेशियलिटी उत्पाद बनाती है। इसकी दो-तिहाई से अधिक आय अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आती है। कंपनी के शीर्ष पांच उत्पादों से करीब 63त राजस्व आना निवेशकों के लिए जोखिम है। इश्यू में ₹1,607 करोड़ का हिस्सा ऑफर फॉर सेल का है, जबकि केवल 150 करोड़ नया पूंजी निवेश है।

2.स्काईवेज एयर सर्विसेज का 582.80 करोड़ का इश्यू भी निवेशकों के आकर्षण में है।

कंपनी एयर और ओशन फेंट फॉरवर्डिंग का कारोबार करती है, उसकी आय का बड़ा हिस्सा एयर फेंट पर निर्भर है। वैश्विक व्यापार, मुद्रा दरों और अंतरराष्ट्रीय नीतियों में बदलाव से कारोबार हमेशा प्रभावित हो सकता है।

3.हाई-टेक इंजीनियर्स, मधुर निट क्राफ्ट्स, एबीएच हेल्थकेयर, अन्नू प्रोजेक्ट्स, सुमैक्स इंजीनियरिंग, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज और क्विक फॉरसिक सॉल्यूशंस के इश्यू भी इसी अवधि में निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं।

निवेशकों को केवल जीएमपी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए।एसएमई कंपनियों में कम कारोबार और ज्यादा उतार-चढ़ाव का जोखिम हमेशा बना रहता है। कंपनी का कर्ज, मुनाफा, प्रमोटर हिस्सेदारी, वैल्यूएशन और आईपीओ से मिलने वाली राशि को देखकर ही फैसला करना बेहतर होगा। कंपनी जिस तरीके से भारी प्रीमियम ले रहे हैं उसमें निवेशकों का जोखिम भी बढ़ है।

निवेशकों को इशायू में सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है।

आईपीओ खुलने आईपीओ बंद कंपनी का नाम की तारीख होने की तारीख फेस वैल्यू प्राइस बैंड रिटेल प्राइस बैंड इश्यू साइज

1सिम्बायोटेक फार्मालैब

24 अगस्त 27 अगस्त ₹2 ₹938-₹988 ₹ 9 3 6 - ₹986 ₹1,757 करोड़

2स्काईवेज एयर सर्विसेज

24 अगस्त 27 अगस्त ₹10 ₹131-₹138 ₹ 1 2 1 -

₹128 ₹582.80 करोड़

3 हाई-टेक इजीनियर्स

24 अगस्त 27 अगस्त ₹5 ₹50-₹53 ₹45-₹48 ₹135.73

करोड़

4 मधुर निट क्राफ्ट्स

24 अगस्त 27 अगस्त ₹10 ₹95-₹100 ₹ 8 5 -

₹90 ₹53.27 करोड़

5 एबीएच हेल्थकेयर

24 अगस्त 27 अगस्त ₹10

₹96-₹102 ₹ 8 6 -

₹92 ₹34.98 करोड़

6 अनु प्रोजेक्ट्स

25 अगस्त 28 अगस्त ₹10

₹94-₹99 ₹84-₹89 ₹175.06

7 सुमैक्स इंजीनियरिंग

25 अगस्त 28 अगस्त ₹10 ₹95-₹101 ₹ 8 5 -

₹91 ₹53.40 करोड़

8 ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज

27 अगस्त 31 अगस्त ₹5 ₹78-₹82 ₹73-₹77 ₹ 7 0 0

करोड़

9 क्विक फॉरंसिक

सॉल्यूशंस 27 अगस्त 3 1

अगस्त ₹10 ₹ 8 5 -

₹90 ₹75-₹80 ₹50.77

करोड़

नोटः सिम्बायोटेक फार्मालैब,

स्काईवेज एयर सर्विसेज, हाई-टेक

इंजीनियर्स, मधुर निट क्राफ्ट्स और

एबीएच हेल्थकेयर के

आईपीओ की तारीखें और प्राइस

बैंड उपलब्ध आईपीओ कैलेंडर के

अनुसार हैं।

रुपया एक पैसे की गिरावट पर बंद	मुबई।
	अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार को एक पैसे की गिरावट के साथ ही 95.71 पर बंद हुआ। आज सुबह अमेरिकी मुद्रा में नरमी के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया सात पैसे चढ़कर 95.64 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव जारी रहने से रुपये की बढ़त सीमित रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर सूचकांक कमजोर हुआ है, लेकिन ब्रेंट कच्चे तेल की ऊंची कीमत और आयातकों की ओर से डॉलर की निरंतर मांग ने रुपये की बढ़त को सीमित किया। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 95.64 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की बढ़त है। रुपया शुक्रवार को केवल तीन पैसे चढ़कर 95.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 फीसदी बढ़कर 98.82 पर रहा।

वोडाफोन आइडिया को एसबीआई से मिली हरी झंडी, प्रवर्तक देंगे गारंटी पूंजीगत व्यय के लिए एसबीआई के ऋण को मिली मंजूरी



नई दिल्ली।

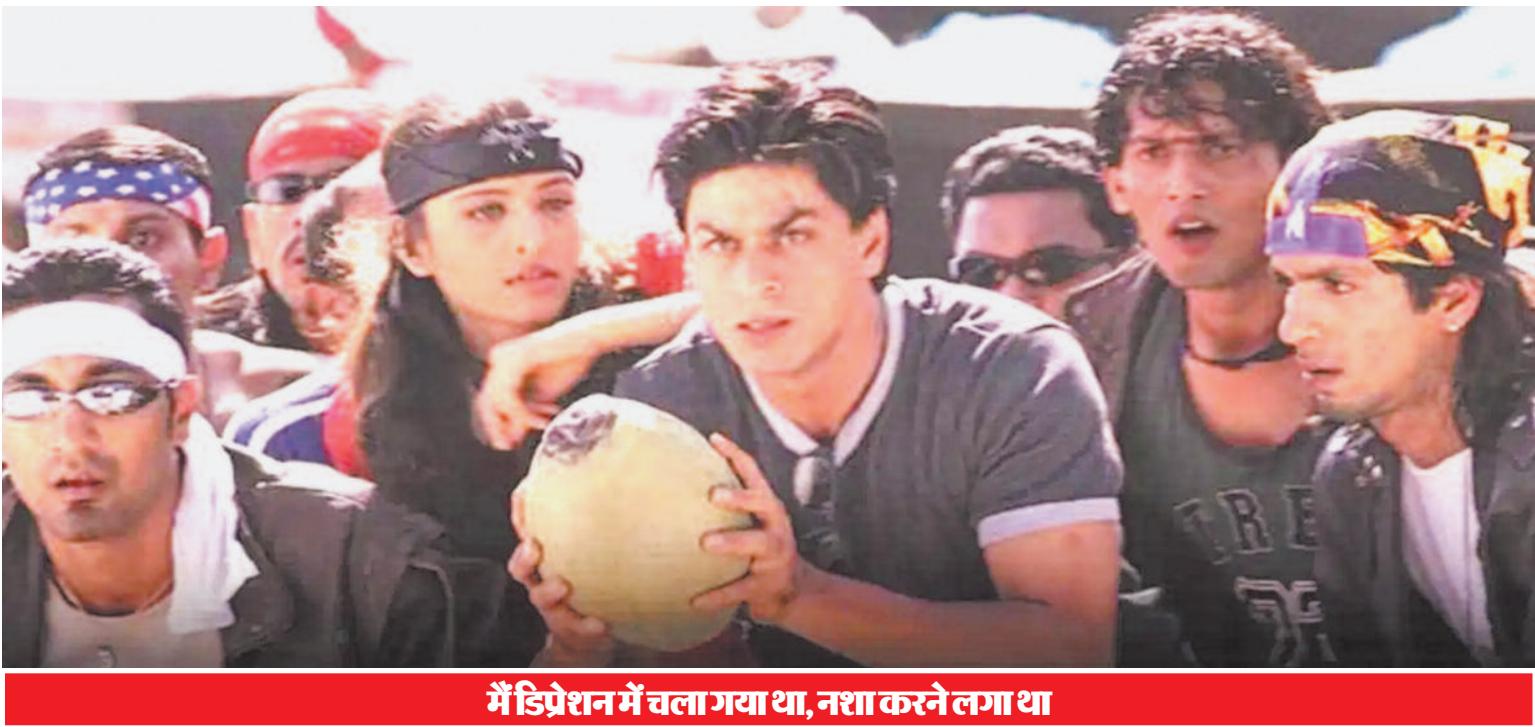
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआई) को अपने पूंजीगत व्यय के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने हिस्से के ऋण को मंजूरी दे दी है, जो पहले प्रवर्तकों की गारंटी न होने के कारण अटक हुई थी। सूत्रों के अनुसार कंपनी के प्रवर्तकों, मुख्य रूप से आदित्य बिड़ला समूह, ने गारंटी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे पहले पैदा हुआ गतिरोध समाप्त हो गया। हालांकि, एसबीआई ने एक शर्त रखी है कि, वह अपनी ऋण राशि तब तक जारी नहीं करेगा जब तक वोडाफोन आइडिया निजी क्षेत्र के बैंकों से शेष आवश्यक ऋण सुरक्षित नहीं कर लेता। एक वरिष्ठ बैंकर ने बताया कि यह गारंटी

प्रवर्तक कंपनियों द्वारा दी जाएगी, न कि समूह की बड़ी सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गारंटी एसबीआई के ऋण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करेगी।

वोडाफोन आइडिया ने चार साल बाद, यदि स्थिति अनुकूल रहती है, तो गारंटी वापस लेने का अनुरोध किया था, जिस पर एसबीआई ने सहमति जताई है। वर्तमान में कंपनी में प्रवर्तकों की कुल 25.64 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और आदित्य बिड़ला समूह शामिल हैं। भारत सरकार की लगभग 49 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन वह एक सार्वजनिक शेरधारक के रूप में वर्गीकृत है। इस मामले पर एसबीआई, वोडाफोन आइडिया और आदित्य बिड़ला समूह से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

मेकअप बेस के रूप में फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे चेहरे की त्वचा चिकनी और समतल बनती है तथा मेकअप को अधिक देर तक रखने के लिए भी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेकअप का आधार होने के साथ-साथ त्वचा की रक्षा भी करता है और इसके इस्तेमाल से क्रीम-मुंहासे, झाँझाँ तथा दाग-धब्बे छिप जाते हैं। फाउंडेशन लगाने का सही तरीका फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे और गर्दन की त्वचा को वेलीजिंग क्रीम या लोशन से साफ करें। उसके बाद रुई की मदद से चेहरे और गर्दन पर फाउंडेशन लगाना चाहिए। फिर अपने चेहरे के विभिन्न हिस्सों पर फाउंडेशन को डॉट्स की तरह लगाएं। फिर अपनी अंगुलियों या ग्लोस स्पे से चेहरे पर अंदर से बाहर की ओर हल्के से मसाज करते हुए फाउंडेशन को मिलाएं। तैलीय त्वचा पर फाउंडेशन लगाने से पहले रुई से एस्टिडेंट लोशन लगाएं। और फिर कुछ देर बाद फाउंडेशन लगाएं। एस्टिडेंट लोशन से त्वचा की चिकनाई दूर होती है। इसी तरह ड्राई स्किन पर फाउंडेशन लगाने से पहले ग्लिसरीन या मॉइश्चराइजिंग पुरे चेहरे पर लगाना चाहिए। सामान्य त्वचा के लिए कोई भी फाउंडेशन चल सकता है, मगर अँध्यारी त्वचा के लिए वॉटर बेस्ड और शुष्क त्वचा के लिए मॉइश्चराइजिंग फाउंडेशन अच्छा होता है। आपकी स्किन ड्राई है, तो फाउंडेशन में दो-तीन बूंद पानी मिलाकर चेहरा पर लगाएं। चेहरे पर फाउंडेशन अधिक न लगाकर उचित मात्रा में ही लगाएं। फाउंडेशन लगाने के बाद टैट्यू पेपर से उसे इकसाकर कर लें और थोड़ी देर सुखने दें। उसके बाद उस पर फेस पाउडर लगाएं। रात और दिन के हिसाब से फाउंडेशन का चयन करना उचित होता है। इसमें गेडल फाउंडेशन नाइट पार्टी के लिए सही होता है। फाउंडेशन का मतलब सिर्फ त्वचा के रंग को बदलना ही नहीं होता, बल्कि त्वचा के निक्टमट रंग से मैच करना होता है। इसलिए फाउंडेशन का चुनाव अपने चेहरे के रंग के अनुसार ही करें। इनका चुनाव आप अपनी स्किन को ध्यान में रखकर कर सकती हैं। बाजार में फाउंडेशन कई रूपों में उपलब्ध है, जैसे लिक्विड, क्रीम, रिटक, पाउडर फॉर्म में। यदि कोई दुर्घिा हो, तो ब्यूटी एक्सपर्ट से पछुने में जरा भी न हचिकें। गर्मियों में फैमरिटय का केक फाउंडेशन हाई हो जाता है। इस स्थिति में फाउंडेशन लगाने से पहले थोड़ा पानी मिलाएं।





मेंडिप्रेशनमें चला गया था, नशा करने लगा था

‘जोश’ में शाहरुख ने कटवाया इस एक्टर का रोल

फिल्म ‘जोश’ दर्शकों को खूब पसंद आई थी. इसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह लीड रोल में थे. फिल्म में पुनीत वशिष्ठ ने भी काम किया था. उन्होंने रोल काटे जाने का दावा किया है

शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और शरद कपूर की फिल्म ‘जोश’ साल 2000 में आई थी. तब फिल्म को काफी पसंद किया गया था और इसके गाने भी खूब चले थे. फिल्म को मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म का हिस्सा अभिनेता पुनीत वशिष्ठ भी थे. उन्होंने फिल्म में शाहरुख खान की गैंग के सदस्य और उनके दोस्त रॉनी का रोल निभाया था. पुनीत ने अब एक

इंटरव्यू में दावा किया है कि फिल्म में शाहरुख खान ने उनके कई सीन कटवा दिए थे. पुनीत वशिष्ठ ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ‘जोश’ फिल्म पर बात की. इस दौरान रोल काटे जाने पर पुनीत वशिष्ठ ने कहा, ‘काफी कुछ कट हुआ.’ जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, ‘मैंने शाहरुख भाई को डांस वगैरह के लिए ट्रेनिंग भी दी है. तो वो मेरी एनर्जी से अच्छी तरह वाकिफ थे. जब मंसूर खान अपने शॉट लगाते थे, तो शाहरुख खान अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते थे. शाहरुख खान 10 फुट की जंप मारते थे तो मैं ऑटोमैटिकली, नॉर्मली, नैचुरली जंप

मारता था तो मेरी जंप 14 फुट की हो जाती थी. तो ध्यान मेरे ऊपर जा रहा था, इसलिए मुझे कट कर दिया. ‘

‘मैं उनकी जगह होता तो... ‘

पुनीत ने बताया कि जब उन्होंने जोश में काम करना शुरू किया था तो उनकी उम्र महज 20 साल थी. उन्होंने कहा, ‘जोश 4 महीने में बनने वाली थी. लेकिन उसको बनने में साढ़े चार साल लग गए. मेरी नासमझी ये थी कि मैंने उसपर गौर किया जो मैंने खोया, उस पर नहीं, जो मैंने पाया. और फिर इस इस ग्रुप ने, तभी एक ग्रुप बन गया था तो कोई नहीं चाहता था कि ये एनर्जी वाला आए तो मुझे फिर ये

सारे ग्रुपिज्म जो अभी ये वृक्ष बन रहा था, ये नेपोटिज्म का, या एक लॉबी का तो उस ग्रुप ने मुझे बहुत अवांइड किया. ‘

डिप्रेशन और नशे में फंसे पुनीत

पुनीत ने बताया कि जब उन्हें इमोनर किया जाने लगा तो वो डिप्रेशन में चले गए थे. वो कहते हैं, ‘डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म, नशा ये सारी चीजों में मैं घुस गया. क्योंकि टैलेंट था, कॉन्फिडेंस था... नॉर्मली ऐसा ही होता फिर तो ये सारी चीजों में गया. तो ये सारी चीजें हवा भी हो गईं मुझ पर. जरा थोड़ा शॉर्ट भी हो गया मैं. लेकिन अभी भगवान की कृपा है. जो हुआ एक प्रोसेस था.

टॉक्सिक के मेगा हैदराबाद प्री-रिलीज इवेंट में अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट का लेवल



मैं बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरे माता-पिता आंध्र के विशाखापत्तनम में बड़े हुए हैं और मेरे पिता इसी शानदार शहर में पले-बढ़े हैं। इसलिए आप सभी के बीच यहां होना बहुत खास है। मैं आपके शहर से बहुत इम्प्रेस हूं। मैं मुंबई से हूँ, इसलिए यहां आना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। आप सभी को ढेर सारा प्यार। अक्षय ने आगे कहा, ‘मैं भी आप सभी की तरह बॉस का बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी सबसे खास बात यह है कि वह एक बेहद प्राउड इंडियन हैं।

मुझे शुरू से पता था कि वह ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं, जिस पर उनके दर्शकों को गर्व हो। एक ऐसी फिल्म जो इंटरनेशनल और ग्लोबल स्केल की हो और जिस पर हम सभी गर्व कर सकें। वहीं, सुदेव नायर ने भी स्टेज पर अपनी एनर्जी से माहौल को और हाई कर दिया। उन्होंने अपने किरदार करुमाड़ी के बारे में बात करते हुए दर्शकों को टॉक्सिक में आने वाली सनक और पागलपन की झलक दी। सुदेव ने कहा, ‘इस फिल्म में मेरा किरदार करुमाड़ी है। उसके अंदर पागलपन है। अब ज्यादा खतरनाक कौन है, ये आप तय कर सकते हैं।

लेकिन हाँ, इस फिल्म में पागलपन बहुत है। ‘ सुदेव ने अपने मलयाली कनेक्शन पर भी दर्शकों के साथ एक प्यारा पल शेयर किया। उन्होंने कहा, ‘यहां इतने सारे मलयाली हैं, इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मैं घर पर हूं। उन्होंने दर्शकों से टॉक्सिक को थिएटर में देखने की अपील करते हुए कहा, ‘जैसा कि सभी ने कहा, हमें टॉक्सिक को थिएटर में जाकर देखना है। ‘ गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में रॉकिंग स्टार यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर नजर आएंगे। यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



बॉबी देओल स्टार सीरीज पर प्रकाश झा ने दी बड़ी अपडेट

क्या ‘आश्रम 4’ की शुरू हुई शूटिंग?

बॉबी देओल की अदाकारी वाली वेब सीरीज ‘आश्रम’ की अगली कड़ी का एलान हो गया है। प्रकाश झा प्रोडक्शंस ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। ‘आश्रम’ सीरीज के सभी पार्ट को दर्शकों ने प्यार दिया है। प्रकाश झा ने नए सीजन का एलान करके फैंस को तहफा दिया है। ‘आश्रम 4’ का एलान करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई है। इसमें मूवी क्लिपबोर्ड नजर आ रहा है। इस पर ‘एक बदनाम आश्रम’ लिखा है। तस्वीर शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने कैप्शन में लिखा ‘एक और आरंभ। आश्रम के नए अध्याय में आपका स्वागत है। जापनाम। आश्रम 4 की शूटिंग हो रही है।



इस एक्ट्रेस से की गई गंदी डिमांड, बोलीं- इंडस्ट्री में कोई Safe नहीं

कंगना शर्मा ने हाल ही में अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने दावा किया कि बचपन में उनके एक रिश्तेदार ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था लेकिन... कंगना शर्मा ने हाल ही में अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने दावा किया कि बचपन में उनके एक रिश्तेदार ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था लेकिन इस बारे में उनके परिवार को आज तक जानकारी नहीं है। कंगना के मुताबिक, वह रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक्ट्रेस ने अपने बचपन की आर्थिक परेशानियों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उस समय उनके पिता कोई काम नहीं करते थे और परिवार के पास अपना घर तक नहीं था। हालात इतने खराब थे कि कई बार खाने के लिए आटा भी दूसरों से मांगना पड़ता था। जिंदगी की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कंगना शर्मा ने यह भी बताया कि करियर के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि इंडस्ट्री में काम पाने की कोशिश के दौरान उन्हें कई असहज परिस्थितियों से गुजरना पड़ा।



कंगना का छलका दर्द

कंगना ने कास्टिंग काउच के अपने अनुभव को याद करते हुए बताया कि हेट स्टोरी 2 की कास्टिंग के दौरान उनके साथ एक बेहद असहज घटना हुई थी। एक्ट्रेस के मुताबिक, वह एक एजेंसी के शख्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थीं। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि वह कितनी बोल्ड हैं। इस पर कंगना ने कहा कि अगर बात एवेंटिंग की हो तो वह किसी भी तरह का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। और मानसिक रूप से काफी बोल्ड हैं। कंगना ने बताया कि उसने मुझे कहा कि अपन पेंटी उतारकर मुझे दो। तो फिर मैंने कहा अभी खाएगा या बाहर चलकर खाएगा। फिर उसने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी बोल्डनेस देख रहा था। तब मैंने उससे कहा कि तुमने अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों को इस तरह तंग किया होगा। इसके बाद कंगना ने बताया कि कास्टिंग काउच किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है और किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी माना कि ऐसी परिस्थितियों में ईसान किस तरह प्रतिक्रिया देता है, यह काफी हद तक उसके अपने फैसले पर निर्भर करता है।

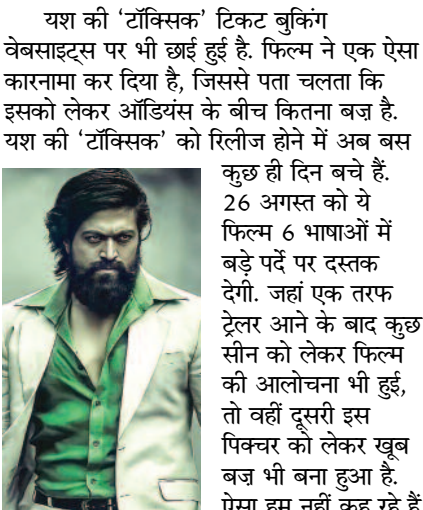
रसिका दुग्गल ने शेयर किया मेलबर्न का अनुभव, कहा- रेखा के साथ ‘उमराव जान’ देखना रहा यादगार



अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में ‘बेस्ट एक्ट्रेस (सीरीज)’ का पुरस्कार जीतकर नया कीर्तिमान हासिल किया है। शनिवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मेलबर्न जर्नी के बारे में बताया। अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने इंस्टाग्राम पर मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल की कुछ झलकियां शेयर कीं। इसमें उनके साथ अभिनेत्री रेखा, रानी मुखर्जी और अभिनेता विजय शामिल हैं। इसके साथ ही स्टेज पर पुरस्कार लेते हुए भी तस्वीर नजर आ रही है। अभिनेत्री ने अपनी इस पोस्ट के जरिए फिल्म फेस्टिवल में यादगार पलों के बारे में बताया। साथ ही, बलासिक उमराव जान देखने के अनुभव को याद किया और रानी मुखर्जी के बारे में एक इमोशनल किस्सा शेयर किया। लिखा, ‘लंबी फ्लाइट्स, एक के बाद एक इवेंट्स जल्दी-जल्दी में किया गया मेकअप, मेरा कैमरा खुद कहता है कि अपना लेंस साफ करो और हेडफोन कभी मिलता ही नहीं। इन सबके बावजूद मुझे हैरान होती है कि मैं हमेशा आईएफएफएम से इंस्पायर्ड होकर लौटती हूं। मुझे एहसास होता है कि पागलपन भरी जिंदगी वाकई में जीने लायक है। अभिनेत्री ने आगे फिल्म प्रोड्यूसर मिटू भूमिक लांगे और स्टाइलिश नताशा समेत पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही, बताया कि अभिनेत्री रेखा कि फिल्म उमराव का असर आज भी बरकरार है। उन्होंने लिखा, ‘रेखा जी और ऐसी ऑडियंस के साथ फिल्म उमराव जान देखना, जो फिल्म के डायलॉग पूरे कर रही थी और गानों के साथ गा रही थी। एक फिल्म का 45 साल बाद भी ऐसा असर हो सकता है। अभिनेत्री ने आगे रानी मुखर्जी की कहानी के बारे में बताते हुए लिखा, ‘रानी मुखर्जी को स्कूल के एक नाटक में शकुंतला के रोल के लिए कास्ट न होने की एक खूबसूरत कहानी सुनाते हुए सुनना - जिससे मैं पूरी तरह से जुड़ पाई। पता चला हम सबकी एक शकुंतला वाली कहानी है और जाहिर है, दिल्ली क्राइम सीरीज के लिए अवांर्ड जीतना भी मेरे लिए खास था। ‘



यश ने रचा इतिहास



यश की ‘टॉक्सिक’ टिकट बुकिंग वेबसाइट्स पर भी छाई हुई है. फिल्म ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है, जिससे पता चलता कि इसको लेकर ऑडियंस के बीच कितना बज्र है. यश की ‘टॉक्सिक’ को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. 26 अगस्त को ये फिल्म 6 भाषाओं में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. जहां एक तरफ ट्रेलर आने के बाद कुछ सीन को लेकर फिल्म की आलोचना भी हुई, तो वहीं दूसरी इस पिक्चर को लेकर खूब बज्र भी बना हुआ है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. दरअसल, ‘टॉक्सिक’ 13वीं ऐसी इंडियन फिल्म बन गई है, जिसे टिकट बुकिंग वेबसाइट बुकमायशो पर 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा इंटरस्ट मिले हैं. फिल्म की रिलीज से पहले बुकमायशो पर फिल्म के नाम के साथ इंटरस्ट का ऑप्शन दिखाता है, जिसके जरिए ऑडियंस फिल्म को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं.

मेरा दिमाग सुन्न हो गया था: करण वाही

टीवी एक्टर करण वाही इन दिनों रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में अपने डर का सामना करते नजर आ रहे हैं। शो के पहले ही हफ्ते में कंटेस्टेंट्स को एक बेहद मुश्किल और दर्दनाक टास्क का सामना करना पड़ा था। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को पैलेट गन से खरब की गोलियां लगाने का दर्द सहना पड़ा था। इस दौरान कई कंटेस्टेंट्स की पीठ पर चोट के निशान भी पड़ गए। अब करण वाही ने इस दर्दनाक टास्क को याद करते हुए बताया कि इसका उन पर कितना असर हुआ था।

दर्द नहीं सह सकते तो छोड़ दो

करण ने जूम के साथ बातचीत में बताया कि शो के होस्ट रोहित शेट्टी आमतौर पर किसी कंटेस्टेंट को हार मानने या शो छोड़ने के लिए नहीं कहते। लेकिन इस टास्क के दौरान उन्होंने कंटेस्टेंट्स से साफ कहा था कि अगर वे दर्द नहीं सह सकते तो पीछे हट सकते हैं। करण ने बताया, ‘क्योंकि ये कोई मजाक या खेल नहीं है। इससे आपको सच में डर लग सकता है और ऐसी चोट लग सकती है, जो आप नहीं चाहते। उस समय सीजन की शुरुआत ही हुई थी। इसलिए आप नहीं चाहते कि शो में आने के बाद या पूरे शो के दौरान आपको बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़े। ‘



संक्षिप्त

समाचार

जापान में भूकंप से कांपी धरती, 20 लोगों के घायल होने की खबर, रिवटर स्केल पर झटके कितने तेज

टोक्यो, एजेंसी। जापान के पूर्वी हिस्से और राजधानी टोक्यो के आसपास रविवार तड़के मध्यम तीव्रता के भूकंप ने लोगों को दहला दिया। प्रारंभिक तौर पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 5.8 दर्ज किया। भूकंप में 20 से अधिक लोग घायल हुए, हालांकि अधिकांश को मामूली चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि सुनामी का कोई खतरा नहीं था। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र इबाकी प्रांत के दक्षिणी हिस्से में जमीन से करीब 70 किलोमीटर की गहराई में था। यह इलाका भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। चार प्रांतों में कुल 23 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। इनमें साइतामा और कानागावा में नौ-नौ, चिबा में चार और इबाराकी में एक व्यक्ति घायल हुआ। अधिकांश लोग उस समय सो रहे थे और अचानक आए तेज झटकों से घबराकर बिस्तर से उठे। इस दौरान कई लोग गिर पड़े या फर्नीचर और दरवाजों से टकरा गए। कानागावा के योकोहामा में 80 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला बिस्तर से गिर गई, जिससे उसके कूल्हे में गंभीर चोट आई। भूकंप के कारण टोक्यो और नािरता हवाईअड्डे को जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों समेत कुछ स्थानीय रेल सेवाएं प्रभावित हुईं और देरी से चलीं। हालांकि शिकानसेन ट्रेनेट ट्रेंड सेवाएं सामान्य रही। टोक्यो के कोटो वार्ड में भूमिगत पानी की पाइप फटने से सड़क पर पानी भर गया, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। भूकंप के बाद करीब 460 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई, लेकिन रविवार सुबह तक बिजली बहाल कर दी गई।

ईरान की अमेरिका को दो-टुक़ : रवैया बदलो तभी खुलेगा होमुज ; पड़ोसी देशों को दी धमकी

तेहरान, एजेंसी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएससी) के सचिव मोहसिन रेजाई ने शनिवार (स्थानीय समय) को दावा किया कि होमुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। समाचार एजेंसी आईआरआईबी को दिए इंटरव्यू में रेजाई ने कहा, अमेरिका के दावों के बावजूद होमुज जलडमरूमध्य बंद है। अमेरिका का रवैया ठीक करने तक यह नहीं खुलेगा। उन्होंने आगे कहा, इस बार अमेरिका को पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। रेजाई ने आरोप लगाया कि वाशिंगटन ने सैन्य विकल्पों की उम्मीद छोड़ दी है। अब वह ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा, सैन्य हमलों से अमेरिकी पूरी तरह निराश है। उन्हें लगता है कि आर्थिक नाकेबंदी के जरिये सैन्य कार्रवाई में मदद की जा सकती है।

मेरिका पर कनाडा का पलटवार : 8 सितंबर से लगाएगा जवाबी टैरिफ, पीएम मार्क ने किया एलान

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ट्रैंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका देश 8 सितंबर से अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी शुल्क (टैरिफ) लगाएगा। इससे पहले अमेरिका ने करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल के कनाडाई सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था। दोनों देशों के बीच इस व्यापारिक विवाद को बातचीत से खत्म करने की आखिरी कोशिश भी शुक्रवार देर रात वाशिंगटन में नाकाम हो गई। कनाडाई प्रधानमंत्री ने क्या कहा प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा के सामान पर जितने डॉलर का टैरिफ लगाएगा, कनाडा भी उतने ही डॉलर के जवाबी टैरिफ अमेरिकी सामानों पर लगाएगा। यह टैरिफ इस्पात, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, कागज बनाने का कच्चा माल और कागज व इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगाया जाएगा। किन्-किन् खास उत्पादों पर टैरिफ लगेगा, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में जारी की जाएगी। क्या अमेरिका की मांगों से बिगड़ी बात कार्नी ने ओटावा में यह भी बताया कि कनाडा इस्पात, एल्यूमिनियम और कारों पर लगाए गए अपने बाकी जवाबी टैरिफ हटाने के लिए तैयार था। लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपने लगाए टैरिफ में बड़ी कटौती करनी थी। कनाडा अमेरिकी शराब की बिक्री दोबारा शुरू करने के लिए अपने प्रांतों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार था। लेकिन अमेरिकी की आखिरी मांगें बहुत ज्यादा थीं। कनाडाई पीएम ने कहा, उन्होंने बहुत ज्यादा मांगा और बदले में बहुत कम दिया।

यूएस ने शुरू किया व्यापार युद्ध: पीएम कार्नी का दावा, क्या ट्रेड डील के सहारे कनाडा के पर कतरना चाहते हैं ट्रंप

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता टूटने के बाद कहा कि उन्होंने खराब व्यापार समझौते के कारण बातचीत से पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका के शुल्क का जवाब देने के लिए समान दर से जवाबी शुल्क लगाने की बात कही। कार्नी ने दावा किया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ऐसी नई शर्तें रखीं, जो आर्थिक रूप से नुकसानदेह और अनुचित थीं। उन्होंने कहा कि इन शर्तों से कनाडा को मिलने वाला कुल मुनाफा कम हो जाता। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्यापार युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। कार्नी ने कहा, जब आप पर हमला होता है तो आप युद्ध में होते हैं। हम पर हमला हुआ।

व्यापार समझौते से कनाडा पर कैसे शिकंजा कसता अमेरिका : कनाडाई पीएम ने कहा, हम उनका पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकते और उन्होंने जो मांगा है, वह हम नहीं

देेंगे। कार्नी ने कहा, अमेरिका ने आखिरी घंटों में दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते करने की हमारी क्षमता को सीमित करने की कोशिश की। आपने मुझे कुछ देर पहले यह कहते हुए सुना कि हमने पिछले एक साल में क्या हासिल किया है- 20 नए समझौते, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी और अपने बाजार तक पहुंचे दोगुनी करने की संभावना। हम मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं।

उन्होंने कहा, दुनिया के कई देशों के लिए हम पसंदीदा साझेदार हैं और अमेरिका इसे सीमित करना चाहता था। उसने ऐसी भाषा का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत इसे सीमित किया जाना था। यह स्वीकार नहीं था।

क्यों टूटा व्यापार समझौता : कार्नी ने कहा, इन शर्तों ने किसी भी समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। संक्षेप में कहें तो उन्होंने बहुत ज्यादा मांगा और बहुत कम पेश किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है

वाशिंगटन, एजेंसी। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ तनाव के बीच अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल के साल के अंत तक पद छोड़ने की चर्चा है। उनके जाने से पहले से नेतृत्व संकट से जूझ रही अमेरिकी सेना पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, हेगसेथ की पत्नी जेनिफर की पेंटागन में बढ़ती भूमिका भी विवाद का विषय बनी हुई है। वह स्टाफ चयन, रणनीति, मॉडिया प्रशिक्षण और सैन्य संचार से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रही हैं तथा संवेदनशील बैठकों में उनकी मौजूदगी पर सैन्य अधिकारियों और सांसदों ने सवाल उठाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप प्रशासन के रक्षा प्रतिष्ठान में नेतृत्व, नियंत्रण लेने की प्रक्रिया और प्रभाव के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

ड्रिस्कॉल के जाने से सेना के शीर्ष नेतृत्व पर असर : ड्रिस्कॉल के पद छोड़ने की स्थिति में अमेरिकी सेना के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का संकट और गहरा सकता है। सेना पहले से ही सीनेट से मंजूर स्थायी चीफ के बिना काम कर रही है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने अप्रैल में सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया था। हेगसेथ ने जॉर्ज को हटाने का कोई सार्वजनिक कारण नहीं बताया था और अब तक उनकी जगह किसी स्थायी अधिकारी को नामित भी नहीं किया गया है।

लानेव संप्रभाल रहे हैं सेना प्रमुख की जिम्मेदारी : जनरल क्रिस्टोफर लानेव, जो सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और पहले हेगसेथ के वरिष्ठ सैन्य



सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं, फिलहाल कार्यवाहक सेना प्रमुख यानी एक्टिंग आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर ड्रिस्कॉल भी पद छोड़ते हैं, तो सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण पद पर बदलाव होगा।

परिवार के साथ रहने की जगह भी बदली : रिपोर्ट के मुताबिक, आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल और उनका परिवार इस गर्मी में जॉइंट बेस मायर-हैंडरसन हॉल स्थित आधिकारिक पारिवारिक आवास से बाहर चले गए थे। उनका परिवार नॉर्थ कैरोलिना चला गया, जबकि ड्रिस्कॉल से खुद सैन्य अड्डे के भीतर एक छोटे अपार्टमेंट में रहने लगे। यह घटनाक्रम हेगसेथ के साथ उनके बिगड़ते रिश्तों के बीच सामने आया है।

हेगसेथ से कब शुरू हुई अनबन : पूर्व आर्मी रेंजर और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पुराने दोस्त ड्रिस्कॉल ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में ही हेगसेथ की नाराजगी का

मुनीर के खिलाफ सेना में असंतोष; रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, छह माह तक तैनात रहेंगी तीन कंपनियां

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिली असमीमित शक्तियों के खिलाफ सेना के अधीनस्थ रैंक अधिकारियों में असंतोष फैल गया है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि गृह मंत्रालय को रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के लिए सेना की तीन कंपनियां तैनात करनी पड़ी हैं। यह तैनाती आले छह माह के लिएहै। हालांकि, सरकार ने इसे राजनीतिक आक्रोश के कारण किसी तरह की संवेदनशील स्थिति से निपटने की कोशिश बताया है।

गृह मंत्रालय ने सेना की तैनाती का आदेश संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत उद्योग गया है, जो नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती का अधिकार देता है। बहरहाल, सूत्रों का कहना है कि हाल में पारित 27वें संविधान संशोधन और नए डिफेंस फोर्स एक्ट के बाद आसिम मुनीर को अभूतपूर्व शक्तियां मिल चुकी हैं। नए ढांचे के तहत मुनीर के पास अब थल, जल और वायु सेना, तीनों अंगों पर पूर्ण नियंत्रण है। मुनीर के पास किसी भी

अधिकारी या जवान को सेवा से बर्खास्त करने और जबरन रिटायर करने के अधिकार आ गए हैं। इससे जूनियर और अधीनस्थ रैंकों के अधिकारी घुटन महसूस कर रहे हैं।

जूनियर अधिकारियों में असंतोष से सैन्य नेतृत्व को संभावित बागवत की आशंका भी सता रही है। पाकिस्तान में हालिया संशोधनों के बाद फील्ड मार्शल मुनीर का कम से कम 2030 तक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। यही नहीं, उन्हें आजीवन कानूनी छूट तथा अभियोग से सुरक्षा भी हासिल हो गई है। इससे सेनाओं के भीतर आंतरिक असंतोष को और हवा मिली है। दरअसल तीनों सेनाओं के कर्मियों को लग रहा है कि उनकी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। रावलपिंडी में सेना की यह ताजा तैनाती ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले शहर के मॉल रोड पर सुरक्षा बलों को एक हमला हुआ था, जिसमें एक अभूतपूर्व शक्तियां मिल चुकी हैं।

नए ढांचे के तहत मुनीर के पास अब थल, जल और वायु सेना, तीनों अंगों पर पूर्ण नियंत्रण है। मुनीर के पास किसी भी अधिकारी या जवान को सेवा से बर्खास्त करने और जबरन रिटायर करने के अधिकार आ गए हैं। इससे जूनियर और अधीनस्थ रैंकों के अधिकारी घुटन महसूस कर रहे हैं।

जूनियर अधिकारियों में असंतोष से सैन्य नेतृत्व को संभावित बागवत की आशंका भी सता रही है। पाकिस्तान में हालिया संशोधनों के बाद फील्ड मार्शल मुनीर का कम से कम 2030 तक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। यही नहीं, उन्हें आजीवन कानूनी छूट तथा अभियोग से सुरक्षा भी हासिल हो गई है। इससे सेनाओं के भीतर आंतरिक असंतोष को और हवा मिली है। दरअसल तीनों सेनाओं के कर्मियों को लग रहा है कि उनकी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। रावलपिंडी में सेना की यह ताजा तैनाती ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले शहर के मॉल रोड पर सुरक्षा बलों को एक हमला हुआ था, जिसमें एक अभूतपूर्व शक्तियां मिल चुकी हैं।

बदमाश को पैसे देने के बाद भी गोलीबारी : पुलिस के अनुसार, आरोपी ने हथियार दिखाकर दुकान में मौजूद लोगों से पैसे लिए। इसके बाद उसने कई राउंड फायरिंग की। एक



कि अमेरिकी मांगों के कुल प्रभाव ने सच्ची आर्थिक साझेदारी के प्रति उत्सुकी प्रतिबद्धता की सीमा विजडा दिया। कार्नी ने कहा कि इसी का दखल है उन्होंने शुक्रवार शाम अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता स्थाित कर दी और कनाडा के वातांकारों को ओटावा लौटने का निर्देश दिया।

शुक्रवार को वाशिंगटन में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बातचीत टूट गई। इसके बाद अमेरिका के 50 प्रतिशत नए शुल्क लागू होने का रास्ता साफ हो गया।

शिकार हो गए थे। तनाव उस समय बढ़ा, जब ड्रिस्कॉल ने वेंस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सैनिकों से मुलाकात और सेना में सुधार की योजनाओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से एक दौरे का आयोजन करने की कोशिश की। हालांकि दोनों के बीच अनबन बनी रही, लेकिन आर्मी सेक्रेटरी के तौर पर अपने करीब 18 महीने के कार्यकाल में ड्रिस्कॉल ने जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ मजबूत कामकाजी रिश्ता कायम किया।

नई तकनीक और भविष्य की जग पर था जोर : ड्रिस्कॉल और

जॉर्ज ने अमेरिकी सेना को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोनों का मानना था कि भविष्य के युद्धों में वाणिज्यिक क्षेत्र से आने वाले नवाचार और तकनीक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ड्रिस्कॉल ने जॉर्ज और जनरल क्रिस डोनाल्ड के साथ यूक्रेन का दौरा भी किया था। उस समय डोनाल्ड यूरोप में अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल थे। इस यात्रा के दौरान ड्रिस्कॉल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की से बातचीत को लेकर भी बातचीत की थी। ड्रिस्कॉल ने अमेरिकी सेना से यूक्रेन के युद्ध से सबक लेने का आग्रह किया। खासतौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेनी सेना युद्ध के मैदान में बाजार में आसानी से उपलब्ध वाणिज्यिक तकनीक का किस तरह इस्तेमाल कर रही है। उनके कार्यकाल के दौरान निजी कंपनियों ने कई परियोजनाओं में 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया। इन

मरीज खुद बने शोधकर्ता: वर्षों तक बीमारी व दर्द से जूझते रहे, अब उसी बीमारी का खोज रहे इलाज वैज्ञानिक

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। बीमारी का सामना करने वाले ज्यादातर लोग इलाज की तलाश में डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी बीमारी को ही शोध का विषय बना लिया। वर्षों तक असहनीय दर्द, गलत निदान और बीमारी के डर से जूझने के बाद इन मरीज-शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला का रास्ता चुना। मकसद सिर्फ खुद के लिए इलाज तलाशना नहीं, बल्कि उन मरीजों के लिए बेहतर उपचार खोजना है जिनकी बीमारियां दुर्लभ या अब तक लाइलाज हैं।

नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक इटली की आर्णविक जीववैज्ञानी फासेस्का ग्रानाटा इसका उदाहरण हैं। बचपन से ही उन्हें त्वचा में इतना तेज दर्द होता था कि मां का गले लगाया भी असहनीय लगता था। 2008 में जांच के बाद पता चला कि उन्हें एरिथ्रोपोएटिक

परियोजनाओं में डेटा सेंटर, महत्वपूर्ण खनिजों की रिफाइनरी और पूरे अमेरिका में सेना के ठिकानों पर डाइनिंग सुविधाओं का विकास शामिल था।

जॉर्ज की बर्खास्तगी से साझेदारी को लगा झटका : ड्रिस्कॉल और जॉर्ज की यह साझेदारी उस समय प्रभावित हुई, जब हेगसेथ ने अप्रैल में अचानक सेना प्रमुख की उनके पद से हटा दिया। हेगसेथ के इस फैसले की कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं ने भी आलोचना की और कई नेताओं ने जॉर्ज के प्रति समर्थन जताया।

कांग्रेस में ड्रिस्कॉल ने जॉर्ज की तारीफ की : कांग्रेस की सुनवाई के दौरान जब ड्रिस्कॉल से जॉर्ज को हटाए जाने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर हेगसेथ की आलोचना करने से परहेज किया। हालांकि, उन्होंने जॉर्ज के बारे में अपनी राय स्पष्ट कर दी। ड्रिस्कॉल ने सांसदों से कहा, मैं ही जनरल जॉर्ज को बहुत पसंद करता हूं। उन्होंने जॉर्ज को एक शानदार और बदलाव लाने वाले लीडर बताया। अपने पद को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, पिछले महीने पेंसिल्वेनिया में आयोजित एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रिस्कॉल की सार्वजनिक रूप से तारीफ की। ट्रंप ने ड्रिस्कॉल के व्यक्तित्व और उनके लुक का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिखने में जितने सीधे-सादे लगते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा सख्त हैं। ट्रंप ने कहा,उनकी मुस्कान कितनी प्यारी है, लेकिन असल में वह एक किलर है।

तेहरान, एजेंसी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने इस्ाइल को हथियार और अन्य समर्थन देने को लेकर फ्रांस और च की आलोचना की है। उनकी टिप्पणी 102 पूर्व ब्रिटिश और फ्रांसीसी राजनयिकों को उस अपील के बाद आई, जिसमें दोनों देशों से इराक़ल पर ठोस दबाव बनाने, हथियारों की आपूर्ति और सैन्य सहयोग रोकने, बर्स्तियों से जुड़े व्यापार पर प्रतिबंध लगाने तथा अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फैसलों को लागू करने की मांग की गई है। राजनयिकों ने वेस्ट बैंक में बर्स्तियों के विस्तार, घरों को गिराए जाने और बसने वालों की हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

लंदन और पेरिस को 'चिंता' के पीछे नहीं छिपना चाहिए : ब्रिटिश और फ्रांसीसी पूर्व राजनयिकों की उस अपील के जवाब में, जिसमें उन्होंने अपनी सरकारों से फलस्तीन में अंतराष्ट्रीय कानून का पालन करने का आग्रह किया था, गरीबाबादी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लंदन और पेरिस को इस स्थिति में सिर्फ चिंता व्यक्त करने की बात कहकर पीछे नहीं छिपना चाहिए। उस शासन को हथियार भेजना और किसी भी तरह का समर्थन देना, जायोजी शासन द्वारा किए जा रहे अपराधों में सहयोग और भागीदारी का जानबूझकर किया गया फैसला है।

100 से अधिक पूर्व राजनयिकों ने उठाई आवाज : गरीबाबादी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब 100 से अधिक



अनुभवी ब्रिटिश और फ्रांसीसी राजनयिकों ने अपनी-अपनी सरकारों को चेतावनी दी है कि इस्ाइल की नीतियां जातीय सफाए और फलस्तीन को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही हैं। उन्होंने लंदन और पेरिस से ठोस कदम उठाने की मांग की है। इनमें हथियारों की आपूर्ति रोकना, इस्ाक़ली बर्स्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाना और हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फैसलों को लागू करना शामिल है। गरीबाबादी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा,100 से अधिक अनुभवी ब्रिटिश और फ्रांसीसी राजनयिकों ने अपनी सरकारों को चेतावनी दी कि जायोजी शासन की नीति 'जातीय सफाए' और 'फिलिस्तीन को खत्म करने' की ओर बढ़ रही है। उन्होंने लंदन और पेरिस से हथियारों की आपूर्ति रोकने, बर्स्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने और हेग अदालतों के फैसलों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।



प्रोटोपोरफोरिया है। यह आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटोपोरफीरिन जमा होने से रोशनी के संपर्क में त्वचा में तेज जलन और दर्द होता है। गंभीर मामलों में यकृत भी प्रभावित हो सकता है।

मां की मौत ने शोध पर किया मजबूर : अमेरिकी वैज्ञानिक सोनिया वल्लभ की कहानी भी ऐसी ही है। 2010 में उनकी 52 वर्षीय मां की तेजी से बढ़ती स्मृतिभ्रंश की बीमारी से मौत हुई। जांच में पता चला कि वह आनुवंशिक प्रायन बीमारी से पीड़ित थीं। बाद में वल्लभ ने भी जांच कराई और पाया कि उनमें भी



इस बीमारी से जुड़ा जीन परिवर्तन मौजूद है। वल्लभ उस समय कानून के क्षेत्र में काम कर रही थीं। मां की मौत और खुद में बीमारी का खतरा सामने आने के बाद उन्होंने करियर बदलकर विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। अब वह अपने पति और संगणकीय जीववैज्ञानी एरिक मिनिकल के साथ प्रायन बीमारी के इलाज पर शोध कर रही हैं।

बीमारी से मिला इलाज का रास्ता : कैसलमैन बीमारी से पीड़ित चिकित्सक-शोधकर्ता डेविड फाजेनबॉम ने अपनी बीमारी के इलाज में पहले से मौजूद दवा के नए इस्तेमाल का रास्ता खोजा। बीमारी के कारण वह कई बार

गोल्डी बराड़ ने क्यों की थी हरदीप निज्जर की हत्या, भगोड़े गैंगस्टर ने लीक ऑडियो में खुद कबूला, बताई असली वजह

टोरंटो, एजेंसी। भगोड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कथित तौर पर एक लीक ऑडियो क्लिप में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने की बात कबूल की है। 2023 में कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ऑडियो क्लिप के अनुसार, बराड़ ने हत्या के पीछे निज्जर द्वारा स्थानीय ड्रा लूट और हिंसा का सामना करने की नेटवर्कों को संरक्षण देने को वजह बताया। साथ ही उत्तरी अमेरिका में अवैध ड्रग्स बेचने के लिए किशोरों का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच गंभीर राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। भारत में कई हत्याओं के मामलों में वांछित गोल्डी बराड़ ने कथित ऑडियो क्लिप में खालिस्तानी चरमपंथी परमजीत सिंह पम्मा से बातचीत के दौरान निज्जर की हत्या की वजह बताई है।

लीक ऑडियो क्लिप में क्या बोला गोल्डी बराड़ : मीडिया रीपोर्ट्स के मुताबिक, बराड़ ने कथित तौर पर चरमपंथी भगोड़े परमजीत सिंह पम्मा को बताया, ये ऑपरेटर 16 से 17 साल के युवाओं को ड्रग्स बेचने के लिए काम पर रखते थे। इसके बाद युवाओं को ब्लैकमेल कर मुखबिर बनने के लिए मजबूर करते थे। निज्जर अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों का समर्थन और संरक्षण करता था, ताकि निज्जर पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। ऑडियो क्लिप के अनुसार उसने आगे कहा, इसीलिए मुझे और मेरी टीम को निज्जर को मारना पड़ा, क्योंकि ये लोग युवाओं का इस्तेमाल ड्रग्स बेचने के लिए कर रहे थे।

निज्जर हत्याकांड से कैसे बिगड़े भारत-कनाडा संबंध :

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके कुछ सप्ताह बाद कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। नई दिल्ली ने इस आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने कनाडा पर अपनी धरती से खालिस्तान समर्थक तत्वों को गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का भी आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे।

कनाडा को नहीं मिला निज्जर की हत्या को भारत से जोड़ने का सबूत : कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों को निज्जर हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश के बाद नई दिल्ली ने अपने उच्चायुक्त और कई अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। कनाडा में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी के संसदीय चुनाव जीतने और ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों देशों के संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने लगे। पिछले महीने कनाडा के जांचकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें निज्जर की हत्या को भारत से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने पिछले महीने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 50 हजार अमेरिकी डॉलर तक का इनाम की घोषणा की थी। एफबीआई ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था, एफबीआई सतिंदर्जीत सिंह की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 50 हजार डॉलर तक का इनाम दे रही है। वह लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध गिरोह में कथित सलिसता के लिए वांछित है।